● वर्ष-5

● अंक-218

रायपुर, बुधवार
29 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित ...

गुजरात में फिर से भगवा परचम...

सभी 15 निगमों में बीजेपी की जीत, सूरत में आप का सूपड़ा साफ

अहमदाबाद› गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुए निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को स्पष्ट कर दिया है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, उसने यह संदेश दे दिया है कि राज्य में उसकी पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है और विपक्ष के लिए उसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। चुनाव परिणामों ने यह भी दिखाया कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व पर कायम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाजपा की इस शानदार जीत के लिए गुजरात के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। हम आपको बता दें कि गुजरात के निकाय चुनावों में भाजपा ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। यह जीत केवल सांकेतिक नहीं बल्कि व्यापक जनसमर्थन का प्रमाण है, क्योंकि हर नगर निगम में पार्टी ने पचास प्रतिशत से अधिक सीटें हासिल कीं। कुल मिलाकर 1044 सीटों में से 856 सीटें जीतकर भाजपा ने अपना दबदबा साबित किया।

यह परिणाम दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण निकायों में भी पार्टी की पकड मजबूत बनी हुई है।

राज्य के सबसे बडे शहर अहमदाबाद में भाजपा ने 192 में से 158 सीटें जीतकर शानदार विजय हासिल की। यह जीत न केवल संगठन की मजबूती को दर्शाती है बल्कि शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता का भी संकेत देती है। अहमदाबाद नगर निगम में इस तरह की जीत से यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा का शहरी वोट बैंक अभी भी अटूट है और विपक्षी दल वहां कोई ठोस चुनौती पेश करने में असफल रहे।सूरत में भी भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 127 में से 115 सीटें अपने नाम कीं। इस परिणाम ने विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए बडी चुनौती खडी कर दी है। पिछले चुनाव में जहां इस पार्टी ने 27 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार वह केवल 4 सीटों तक सिमट गई। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत कमजोर रही और उसे पांच साल बाद केवल एक सीट मिली। सूरत के नतीजे यह दिखाते हैं कि विपक्ष अपनी जमीन बचाने में भी संघर्ष कर रहा है।

सूरत में आम आदमी पार्टी को एक और झटका तब लगा जब उसकी वरिष्ठ नेता और निगम में विपक्ष की नेता पायल सकारिया अपनी सीट हार गईं। यह हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं बल्कि संगठनात्मक कमजोरी का संकेत भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अपने प्रभाव को बरकरार रखने में नाकाम रही और भाजपा के सामने टिक नहीं पाई।

उधर, भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पार्टी नेतृत्व की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को दिया है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और मजबूत आंतरिक सुरक्षा ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय निकाय।

सीआर पाटिल ने जीत के बाद मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि यह जनादेश जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी पिछले लगभग तीस वर्षों से सूरत नगर निगम में सत्ता में है और लगातार जनता के भरोसे पर खरी उतर रही है।

नारी शक्ति से भयभीत हैं परिवारवादी दलः मोदी

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी वंदन सम्मेलन में हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने काशी की महिलाओं को नमन करते हुए कहा कि आज का यह अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे महाराष्ट्र के लोगों को काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या आने के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनकी प्रगति में हर संभव सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ही नए भारत की असली ताकत है, और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लंबे समय तक महिलाएं उपेक्षित रहीं। उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं से सवाल तक नहीं पूछे जाते थे और सीधे निर्णय थोप दिए जाते थे। यह स्थिति केवल काशी ही नहीं, बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में बहन-बेटियों का अनुभव रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह करीब 25 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस सोच को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जिससे अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब देश की माताओं-बहनों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, तब से भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ परिवारवादी दल नारी शक्ति से भयभीत हैं और नहीं चाहते कि महिलाएं विधानसभा और संसद तक पहुंचें। विपक्ष को डर है कि यदि महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीति में आईं, तो उनकी पारंपरिक राजनीति समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सोच नारी शक्ति का सम्मान और नागरिक देवो भव की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे देश को विकसित बनाने के इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करें।उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि वे नारी वंदन के इस प्रयास को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहा कि विपक्षी दलों की वजह से लक्ष्य अधूरा रह गया।

महिलाओं के सशक्तीकरण से देश मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि 30 करोड़ से अधिक बहनों के लिए बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में महिलाओं से कहा कि वे इस कार्यक्रम में महा यज्ञ के प्रारंभ के लिए सभी बहनों और बेटियों का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि काशी के सांसद के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के कल्याण के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है।

दूसरे चरण के चुनाव में राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की अग्निपरीक्षा

कोलकाता। बंगाल की सत्ता का भविष्य बुधवार को ईवीएम में कैद होने जा रहा है। दूसरे और अंतिम चरण का यह मतदान केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, भाजपा की आक्रामकता और तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य किले की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है।

142 सीटों का यह गणित इतना उलझा हुआ है कि यहां एक-एक वोट के लिए संघर्ष दो हाथ वाली लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अंतिम चरण के सामाजिक और सामुदायिक समीकरण बेहद जटिल हैं। सात

जिलों के इस रणक्षेत्र में चार जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल तृणमूल का एकछत्र राज है।

आंकड़ों की गहराई में उतरें तो इन 142 सीटों में से 123 सीटें तृणमूल की झोली में हैं, जबकि भाजपा के पास 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के पास मात्र एक सीट है। ममता बनर्जी के लिए यह अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है तो भाजपा के लिए यह उस दुर्ग को ढहाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का आखिरी रास्ता है। कश्मीर जैसी चौकसी चुनाव आयोग ने इस चरण को %अति-संवेदनशील% की श्रेणी में रखा है।

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, वह बंगाल के चुनावी इतिहास में विरल हैं, दो लाख से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों व पुलिस ही नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर से विशेष रूप से मंगाई गई बुलेटप्रूफ गाड़ियां चुनावी मैदान में तैनात हैं। हर बूथ से लाइव वेबकास्टिंग और 100 मीटर के दायरे में कड़ा पहरा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक मजबूत और संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है, वहीं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभागीय योजनाएँ प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इन प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

प्रमुख समाचार

भारत पहुंची यूएनजीए अध्यक्ष बेयरबॉक ने विदेश मंत्री

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात के बाद

जानकारी साझा कर बताया कि उन्होंने बेयरबॉक के साथ संयुक्त राष्ट्र के 80वें सत्र, सतत विकास लक्ष्यों , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।ताकि यह वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं, खासकर ग्लोबल साउथ की जरूरतों को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित कर सके। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। हालांकि विस्तृत कूटनीतिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया।

होर्मुज को लेकर ट्रंप का नया दावा, ढहने की कगार पर ईरान...

नईदिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ढहने की कगार पर है और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। इलाके में अब भी हजारों जहाज़ फंसे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तेहरान ने व्हाइट

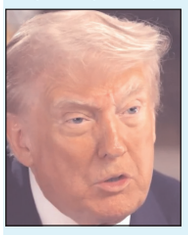

हाउस से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की गुजारिश की है। हालांकि, राष्ट्रपति ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि ईरान ने यह मैसेज किस तरह से भेजा था। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि तेहरान नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट में लिखा, ईरान ने अभी-अभी हमें बताया है कि वे पूरी तरह से ढहने की कगार पर हैं। वे चाहते हैं कि हम होर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोल दें, जिससे वे अपने नेतृत्व की स्थिति पटरी पर ला सकें। यूएस और इज़रायल के बीच हफ़्तों तक चली लड़ाई के बाद भी ग्लोबल ट्रेड का जरूरी रास्ता होर्मुज स्ट्रेट समुद्री यातायात के लिए अभी भी बंद है।

ईरान ढहने वाला नहीं, हम एक मजबूत देशः जियाईनिया

नई दिल्ली। क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला कर सारी हदें पार कर दी हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में मौजूद ईरान के एक बड़े अधिकारी ने मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों पर करारा हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय के उप प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद होसैन जियाईनिया ने साफ कहा है कि

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है और संयुक्त राष्ट्र मूकदर्शक बनकर सब देख रहा है। उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें ईरान के ऊर्जा ठिकानों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी।जियाईनिया ने साफ कर दिया है कि ईरान चुप बैठने वाला देश नहीं है और वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। उनका कहना है कि ईरान पर हमला करने वाले लड़ाकू विमान सीधे अमेरिका से नहीं उड़ सकते, बल्कि वे ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं, जिसमें फलस्तीन की जमीन भी शामिल है। ईरान के अधिकारी ने पूछा है कि अगर आपके घर पर कोई चारों तरफ से हमला करे, तो क्या आप चुप रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक प्रथाओं तक पहुंची बहस

नई दिल्ली। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को अहम बहस देखने को मिली। केरल के सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामलों पर यह सुनवाई जारी है और आज इसका नौवां दिन रहा। मस्जिद और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश के

खिलाफ पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने अदालत में कहा कि हिजाब को कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से आवश्यक मान सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे हर संस्थान में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूलों और अन्य संस्थानों के अपने नियम होते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं से अलग हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई मस्जिद सभी के लिए खुली भी हो, तब भी वहां जाकर अन्य धर्मों की प्रथाएं— जैसे घंटी बजाना या आरती करना, संभव नहीं है, क्योंकि हर धार्मिक स्थल की अपनी मर्यादा और परंपराएं होती हैं।

बंगाल में ममता के तानाशाही शासन का होगा अंतः चिराग

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ''बड़ी जीत'' का दावा करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के ''हिंसक, भ्रष्ट और तानाशाही'' शासन से ऊब चुकी है। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)

की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष पासवान ने पटना में संवाददाताओं से कहा, ''पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के तानाशाही, हिंसक और भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए मतदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के व्यापक चुनाव प्रचार ने लोगों में विश्वास पैदा किया है।'' उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले आया है। उन्होंने दावा किया, ''मुझे पूरा विश्वास है कि चार मई को जिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने वाले हैं, उन सभी में राजग बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूं।''

आप संसदीय दल का टूटना तय था

आशुतोष

यह तो होना ही था। हैरानी इस पर नहीं कि आप क्यों टूटी? हैरानी इस बात पर है कि इतनी देर से क्यों टूटी? आप के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी और भाजपा से जा जुड़े। इन सात में से तीन वे हैं, जो कभी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की आंख और कान हुआ करते थे। उनके पास इतनी पावर थी कि पार्टी के बेहद वरिष्ठ लोग भी उनसे ईर्ष्या करते थे। केजरीवाल उनकी ही सुनते थे। पर उन्हीं लोगों ने बगावत की, जिन्हें पार्टी ने बनाया, संवारा और कम उम्र में पहचान दी। बाहर के लोगों को यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन जो लोग पार्टी चलाने के केजरीवाल के तरीके से वाकिफ हैं, वे जानते हैं कि एक दिन ऐसा होना ही था। दरअसल आप जिन उद्देश्यों के लिये बनी थी, उनसे वह भटकने लगी। जब वह दूसरी पार्टियों की तरह हो गयी और उनकी तरह बर्ताव करने लगी, तब यह होना स्वाभाविक ही था।

जब आप बनी और मुझ जैसे लोग इसमें शामिल हुए, तब यह नारा था, 'हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आये हैं'। लेकिन जैसे-जैसे कारवां बढ़ता गया, सत्ता के खेल में जुड़ता गया, वैसे-वैसे यह नारा फीका पड़ता गया। जो परंपरागत राजनीति को बदलने आयी थी, वह खुद परंपरागत राजनीति का शिकार हो गयी। आज आप और दूसरे दलों में कोई फर्क नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी लाखों-करोड़ों लोग का ख्वाब थी।

वह ख्वाब, जो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता है, जो आम और खास में फर्क न करे, जिसके नेता आम आदमी की तरह रहें। अन्ना आंदोलन ने इस ख्वाब को पंख दिये। जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ता गया, लाखों-करोड़ों लोगों को लगा कि अब देश को भ्रष्टाचारी सिस्टम से मुक्ति मिलेगी, आम आदमी के साथ न्याय होगा, फैसले उसकी सहमति से होंगे और देश में सही मायनों में लोकतंत्र होगा। यह ख्वाब नया नहीं था। यह वह ख्वाब था, जो गांधी, नेहरू और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। गांधी का ऐसा ही नारा था, जिसमें आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के आंसू पोंछने की

बात थी।

ये आदर्श आजादी के बाद कुछ साल चले, पर जल्दी ही सत्तालोलुप लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। अन्ना आंदोलन इस सिस्टम से निकलने की जद्दोजहद का नाम था। इस आंदोलन ने एक राजनीतिक दल का आकार लिया, तो लोगों को लगा कि उनके सपने सच होंगे। एक पार्टी का जन्म के डेढ़ साल में दिल्ली में सरकार बना लेना, दस साल में पंजाब में सत्ता में आ जाना और राष्ट्रीय पार्टी का खिताब हासिल कर लेना सामान्य नहीं था। लेकिन कहते हैं न कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। वही आप के साथ हुआ। आप के नेताओं को सत्ता के स्वार्थ ने डंस लिया। क्रांति के साथी पार्टी छोड़ते गये और दल पर एक आदमी का कब्जा हो गया। जिसने पार्टी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उसी ने पार्टी को निपटाना शुरू कर दिया।

जो पार्टी संगठन और सरकार में पारदर्शिता की बात करती थी, नीति निर्धारण में जन सहभागिता की बात करती थी, आलाकमान कल्चर का विरोध करती थी, हर स्तर पर लोकतंत्र की वकालत करती थी, वह पार्टी एक आदमी में सिमट कर रह गयी। उससे असहमति का अर्थ था सर्वनाश। यह अन्ना आंदोलन की 'एंटी थीसिस' थी। पार्टी में केजरीवाल के अलावा सब रोबोट हो गये। जिनमें जितना सॉफ्टवेयर डाला जाये, बस उतना ही काम करे और आगे के काम के लिये सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार किया जाये। पार्टी में लोकतंत्र खत्म हुआ, तो स्वार्थी लोगों का जमावड़ा होने लगा। इनको समझ में आ गया कि नेता की परिक्रमा करो, विधायक, सांसद और मंत्री बनो।लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। नेतृत्व के लिए उपयोगिता सबसे बड़ा मूल्य हो गयी। चूंकि नेतृत्व को मशीनों की जरूरत थी और हर मशीन की एक एक्सपायरी डेट होती है, लिहाजा हर नेता की, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक एक्सपायरी डेट तय हो गयी। और जब वह डेट आ गयी, तब वह नेता अनुपयोगी हो गया। इसी 'यूज एंड थ्रो' पॉलिटिक्स का नतीजा है कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल जैसे लोग, जो कभी पार्टी में बेहद शक्तिशाली थे, एक्सपायरी डेट के बाद पैदल हो गये। जिनकी नेता के घर में फ्री एंट्री थी और जो हर मीटिंग की शोभा थे, वे फोन कॉल को तरस गये। जब कभी पार्टी एक व्यक्ति में समाहित हो जाती है तब ऐसा ही होता है। दुनिया में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं और भारत में भी।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के पैतृक गांव में बवाल

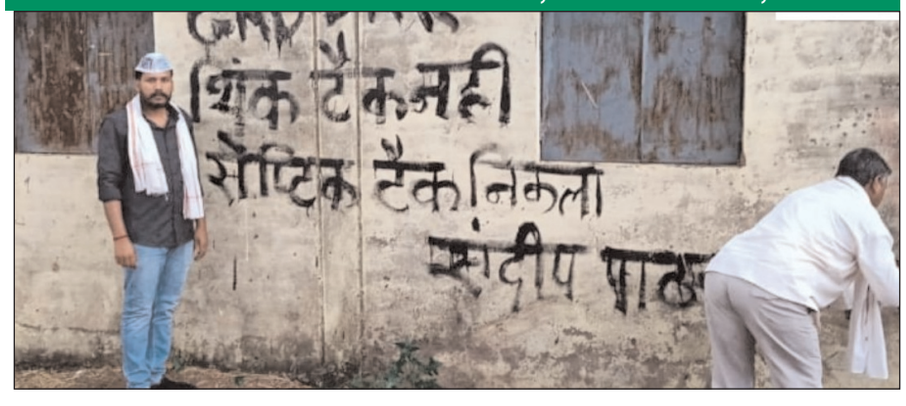

मुंगेली। आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को लेकर छत्तीसगढ़ का भी सियासी पारा बढ़ गया है। इस फैसले से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुंगेली जिले में उनके पैतृक गांव बटहा में घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए घर की दीवार पर ‘गद्दार’ लिखकर अपना विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में जुटे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक पर धोखाधड़ी और अवसरवाद का आरोप लगाते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यह भी लिखा कि संदीप पाठक थिंक टैंक नहीं,

आप कार्यकर्ताओं ने घर की दीवार पर लिखा ‘गद्दार’, कहा- थिंक टैंक नहीं, सैप्टिक टैंक

सैप्टिक टैंक निकले। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उसे छोड़कर उन्होंने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। गौरतलब है कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि 24 अप्रैल, 2026 राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव ने भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी थी। साथ ही अपने साथ कुल सांसदों का समर्थन का भी दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी हैं। पार्टी छोड़ने वाले 7 में से 6 पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं। जबकि एक दिल्ली से है। राज्यसभा सभापति ने राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत आप के 7 बागी सांसदों को क्क्ष्क में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को बाजपा का सांसद मान लिया है। इसे लेकर राज्यसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 7 बागी सांसदों को मिलाकर अब राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 113 पहुंच गई है।

फीस को लेकर डीईओ ने जारी किया कड़ा आदेश, किताब कारोबार पर भी रोक

खैरागढ़। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर आखिरकार प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रही फीस वृद्धि और महंगी निजी किताबों के खेल पर रोक लगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव ने सख्त आदेश जारी किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब लंबे समय से पालक वर्ग निजी स्कूलों की मनमर्जी से परेशान था और लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि जिले के सभी निजी विद्यालयों को छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अब बिना ठोस

कारण फीस बढ़ाना आसान नहीं होगा। खास तौर पर 8 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को इसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों बढ़ाई, किस आधार पर बढ़ाई और किस बैठक में इसकी मंजूरी मिली। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हर स्कूल की फीस समिति में नोडल प्राचार्य की भूमिका अब महज औपचारिक नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें पूरी निगरानी करनी होगी। सबसे बड़ा वार उस किताब सिंडिकेट पर किया गया है, जिसकी आड़ में सालों से अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जाती रही है। आदेश में साफ निर्देश है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को केवल एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाया जाएगा। किसी भी निजी प्रकाशन की किताब थोपना अब सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी किसी खास दुकान या प्रकाशन से किताब खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि शिकायतों को अब अनदेखा नहीं किया जाएगा। एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गांव में बाहरी परिवार को लेकर विवाद धर्म प्रचार के आरोप से बढ़ा तनाव

जगदलपुर। बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावंड गांव में एक परिवार को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से आया यह परिवार कुछ समय से गांव में रह रहा था। ग्रामीणों ने परिवार के गांव में रहने के साथ पास्टर पर धर्म प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों और पास्टर पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना के बाद मामला बस्तर थाना पहुंचा, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। समुदाय की ओर से परिवार के साथ मारपीट, गाली-गलौज और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी व्यक्ति गांव में स्थायी रूप से न रहे और गांव में धर्म प्रचार जैसी गतिविधियां बंद हों, इसी मांग को लेकर विरोध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस

ने गांव के प्रमुखों, सरपंच, कोटवार और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी। बैठक में सहमति बनी कि संबंधित परिवार के बच्चों की परीक्षा समाप्त होने के बाद परिवार गांव छोड़ देगा। फिलहाल मामला शांत हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की हिदायत दी है।

ऑनलाइन आईपीएम सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 6 सटोरियों को दबोचा

रायगढ़। शहर में अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर थाना, कोतवाली और घरघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब ढाई लाख रुपये मूल्य के 7 मोबाइल फोन, 15,490 रुपये नगद और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पहली कार्रवाई में साइबर थाना और कोतवाली पुलिस ने नयागंज कोष्टापारा क्षेत्र

में दबिश देकर सोनू देवांगन (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार किया। वह मोबाइल के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचों पर सट्टा संचालित कर रहा था। उसके मोबाइल से गूगल पे ट्रांजेक्शन और मैच संबंधित स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। इसी दौरान गद्दी चौक स्थित ए-वन कैफे में छापेमारी कर हर्षित देवांगन (उम्र 24 साल) को ऑनलाइन सट्टा चलाते पकड़ा गया। आरोपी मोबाइल के माध्यम से हार-जीत पर दांव लगवा रहा था और डिजिटल पेमेंट के जरिए लेनदेन कर रहा था। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोयल ट्रेडिंग दुकान से भरत गोयल (उम्र 22 साल) को गिरफ्तार किया गया, जो आईपीएल सट्टा संचालित कर रहा था।

नगर पालिका पर पौनी पसारी योजना से लेकर मशीन खरीदी में घोटाले के आरोप

खैरागढ़। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। विकास कार्यों से ज्यादा इन दिनों भुगतान, खरीदी और कथित गड़बड़ियों के मामलों ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति ऐसी है कि ऊपर से सब ठीक, भीतर से सब गड़बड़ जैसी छवि सामने आ रही है। ताजा मामला सरकार की महत्वाकांक्षी पौनी पसारी योजना से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2019-20 में सामान्य सभा की बैठक में पिपरिया वार्ड और इतवारी बाजार वार्ड में बाजार निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। संकल्प क्रमांक-10 के तहत एसडीएम को भूमि आबंटन और शासन को सूचना भेजने का निर्णय लिया गया था। पूरी प्रक्रिया कागजों में नियमों के अनुसार आगे बढ़ी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई। जहां पिपरिया वार्ड में बाजार बनना प्रस्तावित था, वहां आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। इसके विपरीत, करीब चार किलोमीटर दूर इतवारी बाजार में पूरा निर्माण कर दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि टेंडर और अनुबंध दस्तावेजों में निर्माण स्थल पिपरिया ही दर्ज रहा, लेकिन बिना सक्षम अनुमति के स्थल परिवर्तन कर दिया गया। दस्तावेजों के अनुसार सितंबर 2021 में निविदा प्रक्रिया शुरू हुई,

फरवरी 2022 में कार्य एजेंसी से अनुबंध किया गया और तीन महीने में निर्माण पूरा कर भुगतान भी कर दिया गया। भुगतान के दौरान टीडीएस और जीएसटी की कटौती भी की गई, लेकिन मूल सवाल यही है कि स्वीकृत स्थल बदलकर निर्माण कैसे किया गया। इस गड़बड़ी का सीधा असर पिपरिया वार्ड के निवासियों पर पड़ा है, जहां के लोग आज भी सड़क किनारे कारोबार करने को मजबूर हैं। योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल सका, जबकि सुविधा कहीं और विकसित कर दी गई। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बरेठपारा वार्ड में नाली और सीसी रोड निर्माण में भी स्थल परिवर्तन के आरोप सामने आ चुके हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि नगर पालिका में कामों का स्थान बदलना अब अपवाद नहीं, बल्कि एक चलन बनता जा रहा है। इसके अलावा 2021 में खरीदी गई 1000 किलोग्राम क्षमता की लगभग 36 लाख रुपये की कंपोस्ट मशीन भी विवादों में है। मशीन खरीदी तो गई, लेकिन आज तक चालू नहीं हो सकी। इसके बावजूद मरम्मत के नाम पर कई बार भुगतान किए जाने के आरोप हैं।

‘हमर क्लिनिक’ भवन में रहस्यमयी आग, कई दस्तावेज जलकर हुए नष्ट

खैरागढ़। शहर के अमलीपारा वार्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लाखों रुपये की लागत से तैयार किया गया ‘हमर क्लिनिक’ भवन सोमवार देर रात अचानक आग की चपेट में आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह क्लिनिक अब तक मरीजों के लिए शुरू भी नहीं हो पाया था और न ही भवन में बिजली का कनेक्शन चालू है। ऐसे में आग लगने की घटना ने पूरे मामले पर संदेह को और गहरा दिया है।

जानकारी के अनुसार, यह क्लिनिक पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को घर के पास ही नि:शुल्क इलाज, दवाइयां और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन उद्घाटन के लंबे समय बाद भी यहां सेवाएं शुरू नहीं हो सकीं। धीरे-धीरे यह भवन स्वास्थ्य केंद्र के बजाय स्टोर रूम के

रूप में उपयोग किया जाने लगा, जहां राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (ऋक्र्य) से जुड़े दस्तावेज रखे गए थे, जो अब आग में जलकर नष्ट हो गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि भवन में बिजली कनेक्शन चालू नहीं था, इसलिए शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं बनती। इस बयान के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि बिना बिजली के आग लगना

बिना बिजली कनेक्शन के हादसे ने खड़े किए सवाल

सामान्य परिस्थितियों में असामान्य माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे महज दुर्घटना मानने को तैयार नहीं हैं और आशंका जता रहे हैं कि यह किसी साजिश या जानबूझकर की गई हरकत भी हो सकती है। घटना का समय भी संदेह को बढ़ा रहा है, क्योंकि आग रात के समय लगी जब आसपास गतिविधियां बेहद कम थीं। यह क्लिनिक शहर के एक महत्वपूर्ण वार्ड में स्थित है, जहां कई जनप्रतिनिधियों के आवास भी मौजूद हैं। इसके बावजूद न तो भवन में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो सकीं और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। इससे प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग में जले दस्तावेजों में विभागीय कामकाज से जुड़े कागजात शामिल थे, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इनमें कोई संवेदनशील मरीज संबंधी डेटा नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर क्लिनिक समय पर शुरू कर दिया गया होता, तो वहां स्टाफ की मौजूदगी रहती और इस तरह की घटना की संभावना कम हो जाती। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां भवन तो बन जाते हैं, लेकिन सेवाएं आम जनता तक पहुंचने से पहले ही व्यवस्था की खामियों की वजह से दम तोड़ देती हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दूल्हा-दुल्हन ने जलते अंगारों में चलकर पूरी की रस्में

रायगढ़। जिले में एक ऐसी अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन ने पारंपरिक सात फेरों के साथ-साथ जलते अंगारों पर चलकर विवाह की रस्में पूरी कीं। यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि दशकों से आदिवासी समाज में चली आ रही है, जिसे आज भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बिलासपुर गांव में राठिया परिवार के गंधेल गोत्र में यह अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। शादी के बाद जब दुल्हन को घर लाया जाता है, तो घर के देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना के बाद मंडप में जलते अंगारे बिछाए जाते हैं। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन के साथ परिवार के सदस्य नंगे पांव इन अंगारों पर चलकर रस्में पूरी करते हैं। परंपरा के अनुसार, मंडप में बकरे की बलि देने के बाद घर के मुखिया पर देवता सवार होने की मान्यता है। इसके बाद वे नाचते-गाते हुए मंडप में अंगारे बिछाते हैं और पूरे अनुष्ठान का नेतृत्व करते हैं। इस दौरान दूल्हा-दुल्हन समेत कई लोग अंगारों पर चलते हैं।

ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास और जनभागीदारी का सशक्त संदेश

धमतरी। पंचायती राज दिवस के अवसर पर धमतरी जिले में ग्राम लोकतंत्र का सशक्त और जीवंत स्वरूप देखने को मिला। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में 24 अप्रैल से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन आयोजनों ने न केवल ग्रामीण विकास की दिशा तय की, बल्कि जनभागीदारी और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत किया। जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आयोजित ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूह, युवा और किसान शामिल हुए। कार्यक्रमों के दौरान संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों को स्मरण करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की आधारशिला बताया गया। ग्राम सभाओं के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि गांवों का समग्र विकास तभी संभव है।

करोड़ों के बजट के बावजूद अग्निशमन वाहन तक नहीं

एमसीबी। एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी के पास आज तक खुद का अग्निशमन वाहन तक नहीं है। कहीं आगजनी होने पर चिरमिरी को लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के फायर ब्रिगेड वाहन पर निर्भर रहना पड़ता है। शहर के लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके, बाजार, सरकारी कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र में किसी बड़े हादसे की स्थिति बन जाए तो राहत और बचाव कार्य शुरू होने में ही काफी देर हो सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब तक जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन पहुंचेगा, तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। शहरवासियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों, घरों, दुकानों और बिजली ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन अब तक संसाधनों के नाम पर खाली हाथ नजर आ रहा है। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और योजनाओं के दावों के बीच नगर निगम की यह बड़ी कमी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती दिखाई दे रही है।

कन्हर नदी सूखने की कगार पर लेकिन मछुआरों की चांदी

बलरामपुर- रामानुजगंज की जीवनदायिनी कन्हर नदी अप्रैल महीने के अंत से पहले पूरी तरह सूखते ही मछुआरों की चांदी हो गई है। आसपास के गांव के मछुआरे बड़ी संख्या में नदी में पहुंच रहे हैं। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी शुरू होते ही कन्हर नदी सूख चुकी है। नदी का प्रवाह अब थमने की कगार पर है, लेकिन इस आपदा में भी मछुआरा समुदाय के लोग अवसर ढूंढने लगे हैं। यहां सुबह से लेकर देर शाम तक मछुआरे अपने पूरे परिवार के साथ मछली पकड़ने के लिए नदी में पहुंच रहे हैं, जिससे नदी में चहलपहल भी बढ़ गई है। दो दिनों से नदी में मछली पकड़ने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं-मछुआरा जीवनदायिनी कन्हर नदी का पानी अब सूखने की वजह से गर्मी के मौसम में अगले दो महीने मई और जून में पेयजल की समस्या एक गंभीर चुनौती है। नगरपालिका का कहना है कि शहर की बीस हजार की आबादी के लिए जलसंकट की समस्या से निपटने के लिए नदी में डबरी खुदाई कर लोगों के घरों में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है।

प्रशिक्षु डीएसपी निशांत की बोलेरो ही ले उड़ा चोर

अंबिकापुर। पुलिस किसी को पकडने जाए और फिर उसी के साथ कोई वारदात करने का दुस्साहस कर दिखाए तो इसे क्या कहेंगे? कुछ इसी तरह के मामले से पूरा पुलिस महकमा परेशान हो गया। गांजा तस्करों को पकडने के लिए प्रशिक्षु डीएसपी निशांत कुर्रे के नेतृत्व में पुलिस अमला बोलेरो में गया हुआ था कि शातिर चोर मुकेश नामदेव ने कुर्रे का बोलेरो लेकर फरार हो गया। गनीमत रही कि कुर्रे का मोबाइल बोलेरो में ही रह गया और उसके लोकेशन के आधार पर बोलेरो और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, पुलिस ने गांजा तस्करी और बेचने की मिली सूचना के आधार पर छापा मारने का फैसला किया। कोतवाली पुलिस की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ सत्तीपारा गई, जहां उम्मीद थी कि गांजे के साथ तस्कर भी पकड़ा जाएगा। पुलिस वहां पहुंच भी गई थी और गाड़ी छोड़ कर गांजे की खोजबीन करने के लिए पूरा स्टॉफ चला गया। हड़बड़ी में बोलेरो में चाबी लगी रह गई। टीम का नेतृत्व प्रशिक्षु डीएसपी निशांत कुर्रे कर रहे थे।

भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले की जांच तेज

धमतरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने धमतरी जिले के कुरुद में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर दबिश दी। यह कार्रवाई सोमवार सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और देर रात तक चली लंबी जांच के बाद टीम वापस लौटी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम रात करीब 1 बजे तक मौके पर जांच में जुटी रही। इसके बाद जांच पूरी कर टीम वापस रवाना हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। करीब दो थैलों में महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी टीम

अपने साथ ले गई है, जिनकी जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यह पूरी कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में हुए कथित अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है। भूपेंद्र चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। करीब 20 घंटे तक चली इस जांच के दौरान टीम ने दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की और कई अहम सुराग जुटाए। सूत्रों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के बाद मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है।

देवाड़ांड-1 रेत खदान का अधिमानी बोलीदार बने केशल राम

एमसीबी। जिला में खनिज संसाधनों के पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत देवाड़ांड-1 रेत खदान के लिए ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शासन द्वारा रेत खदानों के आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक तकनीकी प्रणाली का प्रभावी उपयोग किया गया। देवाड़ांड-1 रेत खदान के लिए आयोजित इस ई-नीलामी प्रक्रिया में कुल 74 इच्छुक बोलीदारों ने भाग लिया, जो इस खदान के प्रति व्यापक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। तकनीकी परीक्षण एवं दस्तावेजों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद 73 बोलीदारों को पात्र तथा 1 बोलीदार को अपात्र घोषित किया गया।

इसके पश्चात पात्र बोलीदारों के बीच रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया संचालित की गई, जहां एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई जब सभी पात्र प्रतिभागियों द्वारा समान एवं न्यूनतम बोली प्रस्तुत की गई। ऐसी विशेष परिस्थिति में शासन के निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 27 अप्रैल 2026 को इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया गया। यह प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुई, जिससे किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप या पक्षपात की संभावना समाप्त हो सके। इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी के परिणामस्वरूप श्री केशल राम साहू का चयन देवाड़ांड-1 रेत खदान के अधिमानी बोलीदार के रूप में किया गया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पूरी ई-नीलामी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अत्यंत पारदर्शी, निष्पक्ष एवं तकनीकी सुरक्षा मानकों के साथ संपन्न कराई गई है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य खनिज संसाधनों के आवंटन में सुशासन सुनिश्चित करना तथा राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ बनाना है। अधिकारियों के अनुसार अधिमानी बोलीदार के चयन के उपरांत अब आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण की जाएंगी, ताकि देवाड़ांड-1 रेत खदान का संचालन समयबद्ध रूप से प्रारंभ किया जा सके। खदान संचालन शुरू होने से क्षेत्र में रेत की उपलब्धता बेहतर होगी, जिससे निर्माण कार्यों में सुगमता आएगी और अवैध उत्खनन पर नियंत्रण स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

साय कैबिनेट की बैठक आज, विशेष सत्र समेत अन्य मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक 29 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि छठवीं विधानसभा का नवम सत्र 30 अप्रैल को आयोजित होगा। इस सत्र में कुल एक ही बैठक होगी, जिसमें शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस विशेष सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण को लेकर संभावित सियासी टकराव माना जा रहा है। सत्ता पक्ष भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। वहीं कांग्रेस इस विषय पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

गर्मी में पशुओं को लू से बचाएं, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

रायपुर। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान एवं लू (हीट वेव) के प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने पशुपालकों एवं आम नागरिकों के लिए आवश्यक सावधानियां जारी की हैं। बोर्ड ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी में पशुओं को प्रत्यक्ष ताप (डायरेक्ट हीट) के संपर्क से बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मौसम में पशु निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक एवं गर्म सतहों से जलने जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि पशुओं को दिनभर छाया उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त आश्रय की व्यवस्था की जाए। साथ ही पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पशुओं को नियमित रूप से स्वच्छ एवं ताजा पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए चौड़े मुंह वाले ऐसे पात्रों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जिन्हें पशु आसानी से पलट न सकें।

करेन्सी टावर रायपुर में लिफ्ट अवरोध की घटना पर त्वरित जाँच

रायपुर। करेन्सी टावर, रायपुर में स्थापित कैप्सूल लिफ्ट क्रमांक-02 के बीच में रुक जाने की घटना दिनांक 20 अप्रैल 2026 के संबंध में की गई जाँच में यह तथ्य सामने आया है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्टैंडबाय व्यवस्था के रूप में डीजल जनरेटर एवं यूपीएस उपलब्ध है। मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर सभी तकनीकी खामियों को दूर करने हेतु 07 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के दिन विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने पर डीजल जनरेटर के ऑटोमैटिक चेंजओवर सिस्टम में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप यूपीएस भी प्रभावित हुआ और लिफ्ट को निरंतर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी। इसी कारण लिफ्ट बीच में रुक गई। उन्होंने बताया कि उक्त लिफ्ट 23 जनवरी 2027 तक वारंटी अवधि में है एवं संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

31 मई के बाद प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी प्रदेश में शराब

रायपुर। आबकारी मंत्री लखन देवांगन ने मंगलवार को पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा मे कहा कि 31 मई के बाद प्रदेश में शराब प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी। आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से ही प्लास्टिक बोतल में शराब बिक्री का फैसला किया था लेकिन कांच की बोतलों का कारोबारियों ने विरोध किया था। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और अब 1 जून से प्रदेश के सभी शराब दुकानों में प्लास्टिक की बोतलों में शराब मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

सीतारामपुर जलाशय निर्माण कार्य के लिए 6.33 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर जलाशय (बांध) निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ 33 लाख 89 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किये गये हैं। योजना के निर्माण से 150 हेक्टेयर में खरीफ और 50 हेक्टेयर में रबी सहित कुल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

रेगाकठेरा जलाशय योजना के कार्यों के लिए 2.07 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखण्ड-अम्बागढ़ चौकी की रेगाकठेरा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 7 लाख 82 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता 80 हेक्टेयर के विरुद्ध 60 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्यपाल ने ली ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक

सभी स्कूलों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज दुर्ग जिले के प्रवास के दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने निर्देश दिए कि अधिकारी हितग्राहियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक ले। सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून दोनों अवधियों में भूजल स्तर का नियमित और व्यवस्थित मापन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों समयावधियों के आंकड़ों की तुलना करने से यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि वर्षा के साथ-साथ जिले में चलाए गए जल संवर्धन अभियानों जैसे सोखपीट निर्माण और अन्य संरचनाओं का भूजल स्तर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया जाता है, तो न केवल जल स्तर में हो रही वास्तविक वृद्धि का सही आंकलन संभव होगा, बल्कि जल संरक्षण के प्रयासों को और बेहतर दिशा भी दी जा सकेगी।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय भवनों, सड़कों के किनारे तथा सिविल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने को कहा, ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और वे वृक्षारोपण के प्रति अधिक जागरूक एवं प्रेरित होंगे।

राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में धान की खेती अधिक मात्रा में होती है, जिससे पानी की खपत भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को अन्य कम पानी वाली फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर बल देते हुए हाइड्रोपोनिक्स खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स एक उन्नत तकनीक है, जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल के माध्यम से उगाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। बैठक में कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत जिले में 500 किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया है और वे जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।

राज्यपाल श्री डेका ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में शौचालय की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा वे साफ-सुथरे और उपयोग योग्य स्थिति में हों। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों के शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए कहा। राज्यपाल ने यह भी जोर दिया कि शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि ड्रॉपआउट हुए बच्चों और उनके अभिभावकों की बैठकें आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में किसी अच्छे संस्थान में कार्य कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उन्हें स्कूलों में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों से वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और व्यायाम को बढ़ावा देने पर राज्यपाल ने जोर दिया। जिले के 28 संस्थानों में नियमित रूप से योग का अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने सराहना की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में नियमित योग करने वाले प्रतिभागियों की सूची तैयार कर भेजी जाए, ताकि उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया जा सके।

राज्यपाल ने सभी विकासखंड अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, स्कूलों में शौचालयों की स्थिति तथा लखपति दीदी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में किए जा रहे किसी भी नवाचार (इनोवेटिव कार्य) की जानकारी भी ली, ताकि अच्छे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के वेल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि हो सके। साथ ही इन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी गंभीरता जताई और अधिकारियों को इसके लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू करने पर जोर दिया, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया।

बैठक में जिला कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

50 लाख के गबन में फंसे बीरगांव पार्षद, कांग्रेस ने किया निलंबित

रायपुर। राजधानी में 50 लाख रुपए के चर्चित गबन मामले में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीरगांव नगर निगम के पार्षद ओमप्रकाश साहू को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्षद की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया।

खम्हारडीह थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल को कारोबारी के ड्राइवर कृष्णा साहू द्वारा 50 लाख रुपए और कार लेकर फरार होने का मामला सामने आया था। जांच में पुलिस ने ड्राइवर समेत उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों को मिलाकर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पार्षद ओमप्रकाश साहू और दुर्ग जिले के एक सरपंच भी शामिल हैं।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ड्राइवर के जीजा ने गबन की रकम पार्षद को सौंप दी थी। आरोप है कि पार्षद ने पुलिस से बचाने का झांसा देकर पैसे अपने पास रख लिए। उन्होंने 15 लाख रुपए की तस्वीर पुलिस को भेजी, जबकि बाकी 20 लाख रुपए छिपाकर रखने की कोशिश की, ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। हालांकि पुलिस ने बाद में पूरी रकम बरामद कर ली।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने ओमप्रकाश साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पार्टी ने साफ किया है कि संगठन की छवि खराब करने वाले मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पार्षद की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

करेंसी टावर में लिफ्ट फंसने की घटना

जांच में तकनीकी खामियां उजागर, 7 दिन में सुधार के निर्देश

रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर में स्थापित कैप्सूल लिफ्ट क्रमांक-02 के बीच में रुक जाने की घटना (20 अप्रैल 2026) की जांच में तकनीकी खामियां सामने आई हैं। जांच में यह सामने आया है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए डीजल जनरेटर और यूपीएस की स्टैंडबाय व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाया। मुख्य विद्युत निरीक्षकालय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए 7 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के दिन विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने पर डीजल जनरेटर के ऑटोमैटिक चेंजओवर सिस्टम में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप यूपीएस भी प्रभावित हुआ और लिफ्ट को निरंतर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी। इसी कारण लिफ्ट बीच में रुक गई। उन्होंने बताया कि उक्त लिफ्ट 23 जनवरी 2027 तक वारंटी अवधि में है और संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के विनियम 32(7) के तहत 48 घंटे का नोटिस जारी कर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ शासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ऋचा शर्मा करेंसी टावर के लिफ्ट में फंस गई थीं। यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे की बताई गई है, जब वे लगभग 10 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसी रहीं। इस घटना के दो दिन बाद कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली भी इसी तरह की स्थिति का शिकार हुए थे, जिससे लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।

आज आएंगे 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम

■ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 29 अप्रैल बुधवार को जारी होगा। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की है। शिक्षा मंत्री यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं।

बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू हुई थीं, जो 18 मार्च तक चलीं। पहले बोर्ड ने 15 अप्रैल तक परिणाम जारी करने की योजना बनाई थी। हिंदी पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी थी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई।

इस वर्ष हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा में कुल 3,20,535 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) में 2,45,785 छात्रों ने परीक्षा दी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले वर्ष 7 मई 2025 को बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किया था। उस समय कक्षा 10वीं में 68.76% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 82.25% रहा था। अब सभी की नजरें बोर्ड की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों का इंतजार खत्म हो सके।

कॉस्मेटिक दुकानों पर खाद्य व औषधि प्रशासन की सख्ती

रायपुर। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाजार में बिक रहे सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर द्वारा शहर में कॉस्मेटिक दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत की गई। यह विशेष अभियान छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के पालन में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत बाजार में उपलब्ध कॉस्मेटिक उत्पादों की गुणवत्ता, वैधता और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। निरीक्षण के लिए गठित दल में औषधि निरीक्षक श्री टेकचंद धीरहे, श्री ओम प्रकाश यादव, ईश्वरी नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार साहू, श्रीमती प्रीति उपाध्याय और श्रीमती हंसा साहू शामिल थे। टीम ने रायपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों बंजारी रोड, रामदेव मार्केट, गोल बाजार और बंजारी चौक में स्थित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान जवाहर फैंसी, गौरव ट्रेडर्स, राजकमल स्टोर्स, राजा फैंसी, श्री शुभम इमिटेशन, अजय फैंसी स्टोर्स और जय गुरुदेव स्टोर्स सहित कई दुकानों की जांच की गई।

पूर्व मंत्री के भाई के घर श्वष्ठ के छापे पर सियासत गरम

पीसीसी चीफ बैज ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सोमवार तड़के ईडी की टीम ने धमतरी के कुरूद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

दीपक बैज ने कहा कि भारतमाला परियोजना मामले में जांच के तहत उनके भाई के घर छापा पड़ा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह वास्तव में केवल उनके भाई तक सीमित मामला है या फिर पूरा प्रकरण अजय चंद्राकर से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत मिलते हैं।

पीसीसी चीफ ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई के बाद उन्हें बाद में सत्ताधारी दल में शामिल कर क्लीन चिट दे दी जाती है, जो एक पैटर्न जैसा प्रतीत होता है।

दीपक बैज ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि दो संभावनाएं हो सकती हैं- या तो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, या फिर जो नेता विधानसभा में सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता के परिवार तक ईडी की कार्रवाई पहुंची है, जो अपने आप में गंभीर संकेत है।

फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आधिकारिक तौर पर पूरे मामले में दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है।

सदगुरु कबीर आश्रम में मिली 326 वर्ष पुरानी दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की धरती ने एक बार फिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई है। विकासखंड सिमगा के कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा स्थित सदगुरुदेव कबीर आश्रम में कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के दौरान सन् 1700 ईस्वी की 326 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। ये पाण्डुलिपियाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से अमूल्य हैं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रमाण भी हैं। दामाखेड़ा में कुल चार प्राचीन ग्रंथों— अनुरागसागर, अम्बूसागर, दीपकसागर एवं ज्ञान प्रकाश— का सर्वेक्षण कर सरपंच की उपस्थिति में ज्ञानभारतम एप के माध्यम से डिजिटलीकरण पूर्ण किया गया। ये सभी ग्रंथ 9वें आचार्य प्रगट नाम साहब द्वारा लिखित हैं और देवनागरी लिपि में हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इस अभियान की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि सोनाखान संग्रहालय में 10 दिसम्बर 1857 को अंग्रेजी सरकार द्वारा जारी शहीद वीर नारायण सिंह के फाँसी के आदेश की पाण्डुलिपि भी प्राप्त हुई है।

भारतमाला परियोजना घोटाले में शामिल किसी को बख्शा नही जाएगा

रायपुर। भारतमाला परियोजना में चल रही जांच और छापेमारी पर मंत्री टंकराम वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह अधिकारी हो, नेता हो या कोई अन्य व्यक्ति, सभी पर कार्रवाई जारी है और आगे जांच और गहराई तक जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं। सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

रायपुर में मंगलवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह नियमित रूप से होने वाली समीक्षा बैठक है, जिसमें विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन किया जाता है और अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ताकि काम में तेजी और गुणवत्ता बनी रहे।

मंत्री वर्मा ने 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार को लेकर कहा कि यह कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा। विष्णुदेव साय सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता को मिल रहे लाभ की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं का तत्काल निराकरण इस आयोजन की प्राथमिकता होगी।

रायपुर में नाबालिग से जुड़े चाकूबाजी हत्या मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए ही कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। सरकार अपराध और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी सख्ती जारी रहेगी।

डीएमएफ से जुड़े 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों में कथित गड़बड़ियों को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि जहां भी अनियमितताएं सामने आएंगी, उनकी जांच की जाएगी और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिकॉर्ड मतदान के मायने संतोष या सत्ता विरोध

अवधेश कुमार

भारतीय चुनाव में जो कभी नहीं हुआ, वह 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हो गया। अभी तक 92.86 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तमिलनाडु में भी लगभग 85 फीसदी मतदान एक रिकॉर्ड है। अंतिम आंकड़ा आने के बाद इसमें और वृद्धि होगी। बंगाल में 2011 में 84.5, 2016 में 82.56 और 2021 में 81.56 फीसदी मतदान हुआ था। मतदान का दूसरा चरण अभी बाकी है, इसलिए संपूर्ण मूल्यांकन उसके बाद ही होगा। पर चुनाव के दौरान बने माहौल का संकेत यही है कि मतदान की रिकॉर्ड प्रवृत्ति में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। वर्ष 2010 से पहले मतदान प्रतिशत में सामान्य वृद्धि को सत्तारूढ़ पार्टी की पराजय के रूप में देखा जाता था और अधिकतर मामलों में ऐसा ही हुआ। बाद में मतदान बढ़ने के बावजूद सरकारें वापस सत्ता में आती रहीं। इसलिए मतदान प्रतिशत किसी सरकार के जाने या नई सरकार के आने का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग द्वारा विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के कारण अब वास्तविक मतदाताओं के नाम ही बचे हैं। इसलिए हर राज्य में मतदान प्रतिशत थोड़ा संतोषजनक ही होगा। बंगाल में कुल 90 लाख 83 हजार 345 मतदाताओं का नाम सूची से हटा। कई लाख मतदाताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और न्यायिक प्राधिकरणों को फैसला करना है। किंतु 7.66 करोड़ की जगह अब मतदाताओं की संख्या 6.7 करोड़ ही रह गई। इसलिए प्रतिशत ज्यादा होते हुए भी कुल मतों की संख्या इतनी नहीं बढ़ी है। ममता समर्थक और भाजपा समर्थक, दोनों खेमों में मतदाताओं को ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की प्रबल भावना है। भाजपा और उसके विरोधियों की दो ध्रुवीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष, दोनों तरह की लहर देखी गई है। बंगाल में 1967 के बाद से ही मतदाताओं की सुरक्षा हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस, फिर वाम दल और तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनावी रैगिंग या धांधली की प्रवृत्ति को कायम रखा। इस बार मतदाताओं का बड़ी संख्या में निकलने का एक प्रमुख कारण मतदान और उसके बाद के लिए दिखता सुरक्षा आश्वासन था। पहले चरण में केंद्रीय बलों की 2407 कंपनी, 2193 क्विक रिस्पांस टीम व 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जहां कुछ समस्या हो रही थी, केंद्रीय बल तुरंत पहुंचते थे। इसके बावजूद दक्षिण दिनाजपुर के एक भाजपा उम्मीदवार की पिटाई का वीडियो देखने से अनुमान लग जाता है कि माहौल कितना आतंकमय था। चुनाव अभियान के बीच प्रदेश का दौरा करने वालों को 2026 में माहौल में बदलाव दिख रहा था। मतदाता धीरे-धीरे खुलकर अपना विचार प्रकट करने लगे थे। ममता और उनके समर्थकों की आक्रामकता का जवाब भाजपा ने भी प्रति आक्रामकता से दिया। गृहमंत्री अमित शाह तक के भाषणों में आक्रामकता थी, ताकि उनके समर्थक निर्भय होकर मतदान के लिए निकलें। ममता ने भी अपने समर्थकों से कहा कि किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई होगी, तो सरकार साथ खड़ी तो रहेगी ही, हम उन्हें सरकारी नौकरी दे देंगे। यदि मुस्लिम मतदाता भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदान करने निकले होंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया में गैर-मुस्लिम समुदाय भी निकले हैं, जो टीवी कैमरों पर दिख रहे थे। दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, आदि जिलों में दोनों पक्षों में करो या मरो का भाव पैदा हो चुका था। पर जहां एक पक्ष कम रहा, वहां मतदान प्रतिशत कम हुआ और दार्जिलिंग, कालिमपोंग आदि इसके उदाहरण हैं। बंगाल को समझने वाले मानेंगे कि लगातार तीन कार्यकाल के बाद ममता बनर्जी के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान भी है तथा बदलाव के लिए निकलने वाले मतदाताओं की भी भारी संख्या है।

दल-बदल की दस्तक और लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा

विनोद कुमार सिंह

वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य इस समय अस्थिरताओं, वैचारिक टकरावों और सत्ता-संतुलन के नए समीकरणों से गुजर रहा है।यदि भारतीय लोकतंत्र के भीतर झांका जाए तो यहाँ भी कम उथल-पुथल नहीं दिखती।देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की गहमागहमी ने राजनीतिक तापमान को पहले ही ऊँचाई पर पहुँचा दिया है।इसी बीच आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों द्वारा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना इस तापमान को भुचाल में बदलता प्रतीत हो रहा है। यह घटनाक्रम केवल एक दल से दूसरे दल में जाने भर का मामला नहीं है।यह भारतीय राजनीति की उस गहराई को उजागर करता है जहाँ सिद्धांत और स्वार्थ के बीच संघर्ष निरंतर जारी है।

जब हम इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो उस आंदोलन की स्मृति ताजा हो उठती है जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने का दावा किया था।अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला जनलोकपाल आंदोलन केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज नहीं था। वह एक नैतिक क्रांति का प्रतीक बन गया था।इसी आंदोलन की कोख से अरविन्द केजरीवाल ने एक राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी का निर्माण किया। यह एक ऐसा प्रयोग था जिसने पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को अपने मूल सिद्धांतों में शामिल किया। दिल्ली की सत्ता में एक दशक तक बने रहना और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना इस प्रयोग की सफलता का प्रमाण माना गया।किन्तु समय के साथ यह भी स्पष्ट होता गया कि आदर्शों की जमीन पर खड़ी राजनीति को सत्ता के गलियारों में टिकाए रखना सरल नहीं होता।आज जब उसी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद - जिनमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जैसे चर्चित नाम शामिल हैं—दल बदलते हैं, तो यह केवल एक संगठनात्मक संकट नहीं रह जाता।

यह उस वैचारिक प्रतिबद्धता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है जो कभी इस पार्टी की पहचान हुआ करती थी।इस पूरे घटनाक्रम पर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय है।उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ दलबदल विरोधी कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया,वह केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। वह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की पुकार है।उनका यह कहना कि वर्तमान व्यवस्था में नेता व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर पार्टी बदल लेते हैं,भारतीय राजनीति की एक कटु सच्चाई को सामने लाता है। यह सच्चाई किसी एक दल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है।यह एक व्यापक प्रवृत्ति बन चुकी है जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे-धीरे क्षीण किया है।

भारतीय संविधान की आत्मा समाज और राष्ट्र के कल्याण में निहित है।यह किसी राजनीतिक दल के हितों की रक्षा के लिए नहीं बना। जब राजनीति का केंद्र बिंदु सेवा से हटकर सत्ता और संसाधनों के नियंत्रण पर केंद्रित हो जाता है, तब ऐसे विचलन स्वाभाविक हो जाते हैं। अन्ना हजारे ने जिस सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता के दुष्चक्र की बात कही,वह आज की राजनीति का यथार्थ चित्रण है। यह दुष्चक्र केवल भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता, बल्कि जनविश्वास को भी गहरी चोट पहुँचाता है।दल-बदल का यह प्रकरण हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में वैचारिक प्रतिबद्धता अब गौण होती जा रही है।

क्या राजनीतिक दल केवल अवसरवादिता के मंच बनकर रह गए हैं। जब कोई नेता किसी विचारधारा के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करता है और बाद में उसी विचारधारा को त्याग देता है, तो यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता। यह मतदाता के विश्वास के साथ एक प्रकार का विश्वासघात भी है। हालाँकि अन्ना हजारे ने इस घटनाक्रम में सीधे तौर पर सांसदों की आलोचना करने से परहेज किया।उन्होंने अंतिम जिम्मेदारी जनता पर डालते हुए उसे लोकतंत्र का राजा बताया। यह दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है जहाँ अंतिम शक्ति जनता के हाथ में निहित है।

यदि मतदाता जागरूक और विवेकपूर्ण निर्णय ले, तो राजनीति में व्याप्त अनेक विसंगतियों को सुधारा जा सकता है।फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए।क्या केवल मतदाता की जागरूकता ही पर्याप्त है। क्या राजनीतिक दलों और नेताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती।लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता का समावेश अनिवार्य है। यदि इन मूल्यों की अनदेखी होती है,तो लोकतंत्र का ढाँचा भले ही कायम रहे,उसकी आत्मा धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है।भारतीय राजनीति में दलबदल की समस्या नई नहीं है।

साठ और सत्तर के दशक में यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि इसे आया राम,गया राम की संज्ञा दी गई। इसके बाद दलबदल विरोधी कानून लाया गया, लेकिन समय के साथ उसमें कई खामियाँ सामने आईं।आज आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून को अधिक प्रभावी बनाया जाए,ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने जनादेश का दुरुपयोग न कर सके।

वर्तमान घटनाक्रम यह भी संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर पिछले कुछ समय से मतभेद और टकराव की स्थिति बनी हुई थी। यह दर्शाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का सशक्त होना कितना आवश्यक है।जब संवाद और असहमति के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता,तब असंतोष अंततः विद्रोह का रूप ले लेता है।भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन सांसदों का स्वागत किया जाना भी एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हर राजनीतिक दल अपने विस्तार और मजबूती के लिए ऐसे अवसरों का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या केवल संख्या बल बढ़ाना ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, या फिर वैचारिक संगति और नैतिक आधार को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।यह पूरा घटनाक्रम हमें लोकतंत्र के मूल प्रश्नों की ओर वापस ले जाता है। क्या हम केवल सत्ता परिवर्तन को ही लोकतंत्र मानते हैं,या उसके मूल्यों और आदर्शों को भी उतना ही महत्व देते हैं। क्या राजनीति केवल एक पेशा बनकर रह गई है,या यह अभी भी सेवा का माध्यम है।

आज जब देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं,ऐसे समय में मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। यह संदेश है कि वे केवल वादों और नारों के आधार पर नहीं,बल्कि नेताओं के आचरण और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें,क्योंकि अंततः वही लोकतंत्र को मजबूत या कमजोर बनाता है।अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में उभरी राजनीति ने एक समय लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि व्यवस्था को बदला जा सकता है। आज उसी व्यवस्था के भीतर इस प्रकार के घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि परिवर्तन की राह आसान नहीं होती। उसे बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन होता है।

यह समय केवल आलोचना या समर्थन का नहीं है।यह आत्ममंथन का समय है।राजनीतिक दलों को अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि वे अपने मूल सिद्धांतों से कितनी दूर चले गए हैं। मतदाताओं को भी यह तय करना होगा कि वे किस प्रकार की राजनीति को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।अंततः लोकतंत्र की मजबूती किसी एक दल,एक नेता या एक घटना पर निर्भर नहीं करती।यह उस सामूहिक चेतना पर निर्भर करती है जो समाज के प्रत्येक नागरिक में विद्यमान होती है।यदि यह चेतना जागृत और सक्रिय रहती है ,तो कोई भी दुष्चक्र अधिक समय तक टिक नहीं सकता।आज जब भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है,तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम केवल घटनाओं को देखने तक सीमित न रहें।हमें उनके पीछे छिपे संकेतों को भी समझना होगा। यही समझ हमें एक बेहतर,सशक्त और नैतिक लोकतंत्र की ओर ले जा सकती है जहाँ सत्ता नहीं,बल्कि सिद्धांत सर्वोपरि हों।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

नियमपूर्वक प्राण्युत्पादन की क्षमता को प्राप्त करना ही व्रत है तदनुसार जब यह पृथ्वीरूप दिति, प्राणसम्पन्न सृष्टि के निवास योग्य बन जाना रूप पुंसवन-व्रत को कर रही थी उस समय इसके गर्भ में अपरिमित अग्निपुञ्ज विद्यमान था, जिसे पुराण में कनकप्रभम् (62) और अनलप्रभम् (68) श्रादि विशेषणों द्वारा अभिव्यक्त किया है। अस्तु, वह दिति विधि-मोहिता= विधिविधान के तारतम्य से, - संध्या युगारम्भ के अवसर में सो गई अत्यन्त नीरव दशा में अचेत सी हो गई।

उस समय पृथ्वी पर जल का नामोनिशान तक न था, अतएव पुराण में उसे अस्पृष्टवायं-धौतांघ्रिः कहा है (60)। दिति के गर्भ में जो अपरिमित अग्नि-पुञ्ज छुपा हुआ था- कदाचित् वह ज्वालामुखी के रूप में युगपदेव प्रस्फुटित हो जाता तो उससे एक बारगी तो श्राकाशस्थ सभी ग्रह नक्षत्रादि देदीप्यमान देवगण विचलित हो जाते, यही आदित्यानां भयावहम् (66) विशेषण का तात्पर्य्य है। अन्तररिक्षस्थानीय वायु रूप इन्द्र ने असंश्लिष्ट-प्राग्नेय परमाणु-पुञ्ज-भूत, पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करके तदन्तर्गत ऊष्मा को छिन्न भिन्न कर डाला, परन्तु वह ऊष्मा वायव्य परमाणुओं से ऐसी तन्मय हुई कि उसका विश्लेषण करना सर्वथा असम्भव हो गया। यही खण्डशः किये गये मरुतों का इन्द्र के गुट में मिल जाने का तात्पर्य्य है। वेद और पुराण में जिस पार्थिव ऊष्मा का वायु से संश्लिष्ट होना प्रकट किया है वही मरुदु विज्ञान-वादियों के निश्चयानुसार वर्षाकारक मानसून वायु को ही वृष्टि-कारण मानते हैं, तथापि वह वायु कितने प्रकार का है इस बारीकी तक मौजूदा सान्इस अभी तक नहीं पहुंच पाई। यह रहस्य तो कायं.. कारण-पुरस्सर वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध हो सकता है, आस्तां तावत्।

क्रमशः ...

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस

ललित गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूरे विश्व में 29 अप्रैल मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। 'बैले के शेक्सपियर' की उपाधि से सम्मानित एक महान् रिफॉर्मर एवं लेखक जीन जार्ज नावेरे के जन्म दिवस की स्मृति में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप स्थापित किया है।

जीन जार्ज नावेरे ने 1760 में 'लेटर्स ऑन द डांस' नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें नृत्य कला की बारीकियों को प्रस्तुत किया गया। जबकि नृत्य की उत्पत्ति भारत में ही हुई है, यहां की नृत्य कला अति प्राचीन है, कहा जाता है कि यहां नृत्य की उत्पत्ति 2000 वर्ष पूर्व त्रेतायुग में देवताओं की विनती पर ब्रह्माजी ने की और उन्होंने नृत्य वेद तैयार किया, तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य वेद में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद व ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया और जब नृत्य वेद की रचना पूरी हो गई, तब नृत्य करने का अभ्यास भरत मुनि के सौ पुत्रों ने किया। नृत्य के कई प्रकार हैं जिनमें भरतनाट्यम, कुचीपुड़ी, छाउ, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी आदि है।

मनुष्य की प्रवृत्ति है, सुख और शांति की तलाश, जिसमें नृत्य-कला की महत्वपूर्ण भूमिका है। नृत्य खुशी, शांति, संस्कृति और सभ्यता को जाहिर करने की एक प्रदर्शन-कला है। खुद नाचकर या नृत्य देखकर हमारा मिजाज भी थिरक उठता है और हमारी आत्मा तक उस पर ताल देती है। नृत्य जीवन की मुस्कान और खुशियों की बौछार है।

हमारे देश में प्राचीन समय से नृत्य की समृद्ध परम्परा चली आ रही है। नृत्य के अनेक प्रकारों में कथकली प्रमुख है, यह नृत्य 17वीं शताब्दी में केरल राज्य से आया। इस नृत्य में आकर्षक वेशभूषा, इशारों व शारीरिक थिरकन से पूरी एक कहानी को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में कलाकार का गहरे रंग का श्रृंगार किया जाता है, जिससे उसके चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। मोहिनीअट्टम नृत्य भी केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम नृत्य कलाकार का भगवान के प्रति अपने प्यार व समर्पण को दर्शाता है। इसमें नृत्यांगना सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनकर नृत्य करती है, साथ ही गहने भी काफी भारी-भरकम पहने जाते हैं। इसमें सादा श्रृंगार किया जाता है।

ओडिसी ओडिशा राज्य का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आराधना व प्रेम दर्शाने वाला है। इस नृत्य में सिर, छाती व श्रोणि का स्वतंत्र आंदोलन होता है। भुवनेश्वर स्थित उदयगिरि एवं खंडगिरी की पहाड़ियों में इसकी छवि दिखती है। इस नृत्य की कलाकृतियाँ उड़ीसा में बने भगवान जगन्नाथ के मंदिर पुरी व सूर्य मंदिर कोणार्क पर बनी हुई हैं। कथक लोक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें राधाकृष्ण की नटवरी शैली को प्रदर्शित किया जाता है। कथक का नाम संस्कृत शब्द कहानी व कथार्थ से प्राप्त होता है। मुगलराज आने के बाद जब यह नृत्य मुस्लिम दरबार में किया जाने लगा तो इस नृत्य पर मनोरंजन हावी हो गया।

ट्रंप और अमेरिका खुद इतना असुरक्षित क्यों है?

कमलेश पांडे

आखिर दुनिया का थानेदार कहे जाने वाला अमेरिका खुद असुरक्षित क्यों दिखता है? असल में यह एक मिथक और हकीकत का मिश्रण है। अमेरिका के नेता, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के असुरक्षित दिखने के पीछे कई परतें होती हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी वाले स्थल पर यह तीसरा बड़ा हमला है। इसलिए यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक, संस्थागत और वैश्विक कारणों का मिश्रण है।

पहला, वैश्विक नेतृत्व का दबाव : अमेरिका लंबे समय से खुद को विश्व नेतृत्व की भूमिका में रखता है। जब कोई देश या नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तो हर निर्णय पर आलोचना और चुनौती स्वाभाविक होती है-चाहे वह शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था हो या आज की बहुध्रुवीय दुनिया, अमेरिका ने हर चुनौतियों से सीखा और बेहतर समाधान देने की कोशिश की।

दूसरा, घरेलू राजनीति की तीखी प्रतिस्पर्धा: डॉनल्ड ट्रंप की राजनीति बहुत ध्रुवीकृत रही है। अमेरिका के अंदर ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच तीखी टकराहट, मीडिया की आलोचना, और चुनावी दबाव—ये सब किसी भी नेता को रक्षात्मक या असुरक्षित दिखा सकते हैं।

तीसरा, कानूनी और व्यक्तिगत विवाद : ट्रंप कई कानूनी मामलों, जांचों और विवादों से घिरे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क—कभी-कभी असुरक्षित—दिख सकता है।

चौथा, बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन: अब दुनिया एकध्रुवीय नहीं रही। चीन, रूस जैसे देश चुनौती दे रहे हैं। इससे अमेरिका की थानेदार वाली स्थिति पहले जैसी निर्विवाद नहीं रही, और यह असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है।

पांचवां, पॉपुलिस्ट (जनप्रिय) राजनीति की शैली: ट्रंप की राजनीति में हम बनाम वे का नैरेटिव मजबूत रहा है। इस शैली में नेता अक्सर खतरे को बड़ा दिखाते हैं—चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक—

ताकि समर्थकों को एकजुट रखा जा सके। इससे भी असुरक्षा का आभास होता है।

छठा, असुरक्षा का एहसास बनाम असली आंकड़े: अमेरिका में लंबे समय में अपराध दर घटी है, खासकर 1990 के बाद से, लेकिन फिर भी लगभग 46% लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी समस्या सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि डर का माहौल भी है कारण स्पष्ट है कि मीडिया, सोशल मीडिया, और मास शूटिंग जैसी घटनाएं लोगों के दिमाग में डर बढ़ाती हैं।

सातवां, आर्थिक असमानता: अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देशों में है, लेकिन अमीर-गरीब का अंतर बहुत बड़ा है बेरोजगारी, घर विहीनता, श्श्द्ध-श्द्वस्र ष्द्धद्बह्यद्बद्ध जैसी समस्याएं अपराध को बढ़ाती हैं। जहां असमानता ज्यादा होती है, वहां अपराध और असुरक्षा भी ज्यादा होती है।

आठवां, हथियार संस्कृति: अमेरिका में आम नागरिक के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं। इससे छोटी घटनाएं भी घातक बन सकती हैं, जैसे शूटिंग इंसीडेंट्स। यही कारण है कि हिंसात्मक अपराध का डर ज्यादा रहता है।

नौवां, अपराध का केंद्रित होना: पूरे अमेरिका में समान खतरा नहीं है, बल्कि अपराध कुछ खास शहरों या इलाकों में ज्यादा केंद्रित होता है।इसलिए- कुछ जगह बहुत सुरक्षित है पर कुछ जगह बहुत खतरनाक।

दसवां,, मीडिया और राजनीति का प्रभाव: लगातार चौबीस घण्टे सातों दिन न्यूज और सोशल मीडिया खतरे को अम्प्लीफाय करते हैं। लोग वास्तविकता से ज्यादा डर महसूस करते हैं। भय अर्थव्यवस्था भी एक फैक्टर है।

ग्यारहवां, पुलिस और सिस्टम की सीमाएँ: अमेरिका पुलिस और जेल पर बहुत खर्च करता है, फिर भी मूल कारणों, जैसे- गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए सुरक्षा का ढांचा प्रतिक्रियावादी है, सुरक्षात्मक/संरक्षात्मक कम।

बारहवां, सामाजिक व्यवहार और जीवनशैली- सड़क हादसे, नशा, मानसिक तनाव—ये भी असुरक्षा के बड़े कारण हैं कई मामलों में व्यवहार भी जिम्मेदार है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अमेरिका कमजोर नहीं है, लेकिन-आर्थिक असमानता, हथियार संस्कृति, सामाजिक तनाव और मीडिया द्वारा बढ़ा डर आदि के कारण एक शक्तिशाली देश भी अंदर से असुरक्षित महसूस करता है।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप की हालिया सुरक्षा चूक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर (25 अप्रैल 2026) के दौरान हुई, जब एक संदिग्ध ने होटल में घुसकर गोली चलाई। अमेरिकी अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित समय सारिणी घोषित नहीं की गई है। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर के दौरान एक संदिग्ध (कोल एलन) ने शॉटगन, पिस्तौल और चाकू लहराते हुए सिक्योरिटी चेकपॉइंट तोड़ा और गोली चलाई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत नेताओं को सुरक्षित निकाला; एक एजेंट को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ वेस्ट से बच गया। बहरहाल, जांच की स्थिति यह है कि स्नब्ल्ल्ड्ढ की एंटी-टेरर यूनिट जांच लीड कर रही है, जिसमें हथियार, गवाह बयान और संदिग्ध के मैनिफेस्टो की पड़ताल शामिल है। एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि संदिग्ध ट्रंप व उनकी टीम को टारगेट बना रहा था, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। ट्रंप ने इसे सिक्योरिटी सक्सेस बताया, पर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठे हैं। आखिर जवाब कब? तो अधिकारियों ने लाइव अपडेट दिए हैं, लेकिन सुरक्षा चूक के सवालों (जैसे चेकपॉइंट कैसे टूटा) पर कोई अंतिम रिपोर्ट या सुनवाई की तारीख की घोषणा नहीं हुई। जांच जारी है, अतिरिक्त विवरण आने पर बयान संभव। इससे पहले ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 के हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की जांच में जुलाई 2025 में जारी अमेरिकी सीनेट रिपोर्ट ने सीक्रेट सर्विस की गंभीर चूक उजागर की। यह 2026 की हालिया घटना से जुड़ी नहीं, बल्कि पुरानी घटना पर आधारित है।

मुख्य निष्कर्ष यह है कि विश्वसनीय खुफिया सूचना के बावजूद सीक्रेट सर्विस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की; खतरे को नजरअंदाज किया। वहीं, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय की कमी, खासकर पास की छत को सुरक्षित न करना। संचार, तकनीकी और मानवीय चूकें; कोई बड़ा अधिकारी बर्खास्त नहीं, सिर्फ 6 पर हल्की कार्रवाई। इसलिए सिफारिशें की गईं कि जिम्मेदारों को दंडित करने, सुरक्षा सुधार और तालमेल मजबूत करने की मांग की। चेयरमैन रैंड पॉल ने इसे पूरी विफलता बताया। सीक्रेट सर्विस ने स्वीकार किया और सुधार शुरू किए। सीक्रेट सर्विस ने 2024 ट्रंप हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की चूक के बाद कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें एजेंटों पर कार्रवाई और प्रक्रियागत बदलाव शामिल हैं। ये कदम सीनेट रिपोर्ट (2025) के बाद तेज हुए। वहीं, एजेंटों पर कार्रवाई हुई। 6 एजेंटों को सस्पेंड किया, 10-42 दिनों की सैलरी कटौती और गैर-ऑपरेशनल पदों पर स्थानांतरित। पूर्व डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दिया। वहीं, प्रक्रियागत सुधार किए गए। स्थानीय पुलिस/एजेंसियों के साथ समन्वय, संचार और सुरक्षा मैनुअल को संशोधित। हवाई निगरानी के लिए अलग डिवीजन, खतरे मूल्यांकन में स्पष्ट जिम्मेदारियां। कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया।

आज का इतिहास

- 1882 दुनिया का पहला ट्रॉलीबस आपरेशन बर्लिन में शुरू किया गया।
- 1903 कनाडा के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की मौत।
- 1910 यूनाइटेड किंगडम की संसद ने पीपुल्स बुडगेट को पारित किया, ब्रिटिश इतिहास में पहला बजट ब्रिटिश जनता के बीच धन के अविरल योगदान के इरादे से था।
- 1946 सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण ने हिदेकी तोजो और 27 अन्य जापानी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए प्रेरित किया।
- 1965 पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने सातवें रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया।
- 1968 विवादास्पद म्यूजिकल हेयर, 1960 के हिप्पीकाउंटर-संस्कृति और यौन क्रांति का एक उत्पाद, ब्रॉडवे पर बिल्टमोर थिएटर में खोला गया, जिसमें इसके गाने थेन्ती-वियतनाम युद्ध आंदोलन के गान बन गए।
- 1970 वियतनाम युद्ध-दक्षिण वियतनामी सेना ने कम्युनिस्ट जंगल के ठिकानों पर हमला करने के लिए कंबोडिया में घुसपैठ शुरू की।
- 1991 क्रोएशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1991 बांग्लादेश में चक्रवात का हमला, 139,000 लोग मारे गए / 10 लाख बेघर
- 1992 27 वें एकेडमी ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड्स- गार्थ ब्रूक्स।
- 1993 पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया और जिसे देखने के लिए आठ पाउंड का टिकट लगा।
- 1994 इज़राइल और पीएलओ आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।
- 1997 1993 के रासायनिक हथियार सम्मेलन प्रभावी रूप से चले गए, जो हथियारों के नियंत्रण समझौते की पुष्टि करने वाले देशों के रासायनिक हथियारों के उत्पादन, संग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है।
- 1997 रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू।
- 2010 आर्थिक नुकसान माउंट और क्लास एक्शन मुकदमे दायर किए जाते हैं क्योंकि अमेरिकी तटरक्षक ने दीपवाटर होराइजन आपदा से तेल निकालने के लिए एक नियंत्रित जला योजना बनाई।
- 2011 ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का विवाह हुआ।
- 2012 जासूसी के आरोप में, सूडान ने दक्षिण सूडा के साथ विवादित सीमा क्षेत्र में चार विदेशियों को गिरफ्तार किया।

राघव चढढा ने खोद दिया आम आदमी पार्टी का गड्ढा

मनोज कुमार अग्रवाल

भारतीय राजनीति में दल बदल और आंतरिक बगावत कोई नई बात नहीं है लेकिन जब किसी उभरती हुई पार्टी के भीतर इस तरह का बड़ा घटनाक्रम सामने आता है तो उसके दूरगामी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाल ही में राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने अथवा दल-बदल/विलय के दावे से भारतीय राजनीति में कई गंभीर समस्याएं और विवाद उत्पन्न हो गए हैं। यह सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा है कि क्या चड्ढा के साथ अन्य सांसदों का विलय संवैधानिक है। यह दलबदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता और उसके दो-तिहाई वाले प्रावधान पर बहस छेड़ता है कि क्या सांसदों का एक बड़ा समूह रातों-रात पार्टी बदल सकता है।

इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरोप है कि उसके 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक अस्तित्व का संकट है।

पार्टी के पूर्व सहयोगियों और समर्थकों की ओर से इसे वैचारिक विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है। आप ने आरोप लगाया है कि यह ऑपरेशन कमल के तहत भाजपा द्वारा उसके सांसद नेताओं को तोड़ने की कोशिश है।

राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था, जिसके बाद यह बगावत हुई। यह पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व की पकड़ को उजागर करता है।इस प्रकार के बड़े पैमाने पर दल-बदल से अस्थिरता का युग वापस आने की चिंता बढ़ गई है, जिससे लोकतंत्र के भविष्य पर सवाल उठते हैं।

आपको पता है कि राघव चड्ढा और उनके साथ कई राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। यह केवल व्यक्तियों का दल बदल नहीं बल्कि एक संगठन की आंतरिक स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के समय खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। ईमानदारी पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को केंद्र में रखकर इस पार्टी ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। दिल्ली में लगातार जीत और पंजाब में सरकार बनाना इस बात का प्रमाण था कि जनता ने इस पार्टी को स्वीकार किया है। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी के भीतर असंतोष और टूट सामने आ रही है वह यह संकेत देता है कि अंदरूनी ढांचे में कहीं न कहीं कमजोरी मौजूद है।

राघव चड्ढा का पार्टी से अलग होना अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उनके

और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें सामने आती रही थीं। महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने की कोशिश और संगठनात्मक गतिविधियों से दूरी यह सभी संकेत पहले से मौजूद थे। जब उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। इसके बाद उनका इस्तीफा और फिर भाजपा में शामिल होना एक तय दिशा की ओर बढ़?ता कदम प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दो तिहाई सांसदों का गणित। भारतीय संविधान के तहत दल बदल कानून यह कहता है कि यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि राघव चड्ढा ने अपने साथ पर्याप्त संख्या में सांसदों को जोड़ने का प्रयास किया। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था जिससे उनकी संसदीय स्थिति बनी रहे।

यहां सवाल उठता है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है या फिर पार्टी की कार्यप्रणाली में वास्तविक समस्याएं हैं। जब एक दो नहीं बल्कि कई सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो यह संकेत देता है कि असंतोष व्यापक है। स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं का पहले से असहज होना और अन्य नेताओं का अचानक अलग होना यह दर्शाता है कि संवाद और विश्वास की कमी रही है। अब तुलना शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से की जा रही है। इन दोनों दलों में भी इसी तरह की टूट देखने को मिली थी जहां दो तिहाई विधायकों के अलग होने से पार्टी का नियंत्रण बदल गया। हालांकि वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी के मामले में यह टूट राज्यसभा तक सीमित है इसलिए सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन यदि यही स्थिति पंजाब विधानसभा तक पहुंचती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

पंजाब इस समय आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत आधार है। यदि वहां भी इसी तरह का असंतोष पैदा होता है और बड़ी संख्या में विधायक अलग होते हैं तो पार्टी की पहचान और अस्तित्व दोनों पर खतरा आ सकता है। इसलिए यह घटनाक्रम केवल एक संसदीय बदलाव नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घटनाक्रम कई मायनों में लाभकारी है। पहला राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ेगी।

राघव चड्ढा के साथ आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे उच्च सदन में भाजपा की संख्या बढ़कर 113 हो गई है और उसे अहम विधेयकों को पास कराने में आसानी होगी।

यह दलबदल आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और दिल्ली में एक बड़ा झटका है, जहाँ चड्ढा एक प्रमुख युवा चेहरा थे।चड्ढा का रोल सिर्फ टीवी और संसद तक सीमित नहीं था. पंजाब में संगठन खड़ा करने और दिल्ली-पंजाब के बीच समन्वय बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. उनके जाने से यह कनेक्शन कमजोर पड़ सकता है. खासतौर पर तब, जब आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है. इससे भाजपा को पंजाब चजहाँ अगले साल चुनाव होने हैं में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

राघव चड्ढा की छवि एक पढ़े-लिखे, आक्रामक और सलीकेदार प्रवक्ता की है, जो भाजपा के मीडिया और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को और अधिक धारदार बना सकती है।

चड्ढा ने पार्टी द्वारा अपने मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया है, जिससे भाजपा को आप के खिलाफ अपने 'भ्रष्टाचार' के नैरेटिव को और मजबूत करने का मौका मिल गया है।

चड्ढा के साथ आने से उन विधायकों और कार्यकर्ताओं के भी भाजपा में आने की संभावना बढ़ गई है, जो पंजाब और दिल्ली में उनके प्रभाव में थे।

कुल मिलाकर, यह कदम न केवल भाजपा के संख्या बल को बढ़ाता है, बल्कि आम आदमी पार्टी की साख पर भी सवाल उठाता है। राजनीति में हर खबर अपने साथ एक मैसेज भी लेकर आती है. चड्ढा जैसे नेता का बीजेपी में जाने का मतलब है कि बीजेपी विपक्ष के सॉफ्ट, अर्बन और प्रोफेशनल स्पेस में एंट्री चाहती है और आप के भीतर स्थिरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

राघव चड्ढा की एंट्री से बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो उसके विस्तार को नया आयाम दे सकता है और आप को पहली बार अपने ही बनाए नैरेटिव की असली परीक्षा देनी पड़ेगी. सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ एक नाम की कहानी है, या आने वाले समय में सियासत का नया ट्रेंड? को पहली बार अपने ही बनाए नैरेटिव की असली परीक्षा देनी पड़ेगी. सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ एक नाम की कहानी है, या आने वाले समय में सियासत का नया चेहरा दिखाएगा?

बंगाल में भाजपा ने मिटा दिया बाहरी होने का ठप्पा

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा, जिस पर लंबे समय से बाहरी होने का आरोप लगता रहा, उसने इस धारणा को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह पार्टी के नेता स्थानीय खानपान, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़ते नजर आए हैं, उससे बंगाल के लोगों के बीच यह संदेश गया है कि यह दल अब बाहरी नहीं, बल्कि अपना ही है। स्थानीय भोजन के साथ जुड़ाव ने इस राजनीतिक दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है और मतदाताओं के मन में अपनापन पैदा किया है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में इस बार राजनीति और भोजन का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यह केवल प्रचार का तरीका नहीं, बल्कि पहचान, सांस्कृतिक जुड़ाव और स्वीकार्यता का प्रतीक बन गया है। जिस तरह फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी फिल्मों में काशी को बंगालियों के दूसरे घर के रूप में दिखाया था, ठीक उसी तरह अब राजनीतिक दल बंगाल के लिए अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय खानपान को एक प्रमुख माध्यम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारग्राम में झालमुरी खाना हो या अन्य नेताओं का मछली के साथ प्रचार करना, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लंबे समय से बंगाल में बाहरी होने के आरोप से जूझ रही भाजपा का स्थानीय भोजन को अपनाना एक संकेत है कि वह खुद को बंगाल की संस्कृति के करीब दिखाना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खासतौर पर भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि पहचान और जुड़ाव का माध्यम बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में बाहरी का अर्थ केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह भाषा, व्यवहार और खानपान से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इस बाहरी मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया था। इसी के बाद अब भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और स्थानीय संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में भाजपा के कई नेता जैसे अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए नजर आए, वहीं कुछ उम्मीदवार मछली हाथ में लेकर प्रचार करते दिखे। विशेषज्ञों के अनुसार, मोदी का झालमुरी खाना एक सुरक्षित और संतुलित विकल्प था। चूंकि वह शाकाहारी हैं, इसलिए उनके लिए मछली खाना संभव नहीं था। हम आपको बता दें कि बंगाल का खानपान अपने आप में विविधता से भरा है। इसमें इस्लामी, डच और अंग्रेजी प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही घोटी और बंगाल समुदायों के बीच भी भोजन को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में झालमुरी एक ऐसा विकल्प है जो हर वर्ग में समान रूप से स्वीकार्य है। यह सस्ता, सरल और सर्वव्यापी है, इसलिए राजनीतिक रूप से भी सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा, चुनावी माहौल में केवल नेता ही नहीं, बल्कि मीडिया भी इस भोजन राजनीति का हिस्सा बन गया है। विभिन्न समाचार चैनल और पत्रकार चुनाव कवरेज के दौरान स्थानीय भोजन को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। कहीं किसी होटल से चर्चा हो रही है तो कहीं सड़कों पर खाने के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इस तरह भोजन अब एक समाचार विषय भी बन गया है। वैसे जब कोई नेता स्थानीय भोजन खाता है तो वह यह संदेश देना चाहता है कि वह उस जगह का हिस्सा है। लेकिन जब यह सब कैमरे के सामने किया जाता है, तो यह कृत्रिम भी लग सकता है।

पंजाब में आप सरकार की हिल सकती है नींव

कमलेश पांडे

दिल्ली के बाद भाजपा अब पंजाब से भी आम आदमी पार्टी को बेदखल करेगी। इसी के चलते उसने ऑपरेशन लोटस राज्यसभा को अंजाम दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उपनेता पद से हटाए जाने के बाद हाल ही में आप छोड़कर भाजपा में खुशी खुशी शामिल होने का ऐलान किया, जिसमें राज्यसभा के दो-तिहाई आप सांसद (लगभग 7 में से 10) उनके साथ हैं। इससे साफ है कि अब पंजाब में आप की सरकार भी हिलाई जाएगी।

संविधान के जानकार बताते हैं कि चड्ढा का यह कदम संविधान के विलय प्रावधानों के तहत लिया गया, जिससे आप को संसदीय ताकत में बड़ा झटका लगा। लिहाजा, इसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद राघव चड्ढा ने गत 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वे संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत अन्य सांसदों के साथ बीजेपी में विलय कर रहे हैं। उन्होंने आप पर सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया। आप ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया, लेकिन विलय के कारण एंटी-डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता।

चूंकि भाजपा के लिए यह अप्रत्याशित लाभ की स्थिति है क्योंकि बीजेपी को युवा, वाक्पटु और शहरी चेहरे के रूप में चड्ढा मिला, जो विपक्ष के सॉफ्ट वोट बैंक में घुसपैठ करेगा। राज्यसभा में संख्या बढ़ेगी और दिल्ली-पंजाब में आप के संगठन को कमजोर करने में मदद मिलेगी। यह नैरेटिव वॉर में बीजेपी को बढ़त देता है, जहां चड्ढा आप मॉडल पर सवाल उठा सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि जनहितकारी मुद्दों को लेकर चड्ढा ने सोशल मीडिया में एक अभियान चलवाया था और राज्यसभा में भी आमलोगों के मुद्दे को उठाया, जिससे उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी और भाजपा ने उन्हें हाथोंहाथ लोक लिया।

समझा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। इससे आप भी भावी रणनीति पर गहरा प्रभाव

पड़ेगा। जहां तक आप पर प्रभाव की बात है तो आप की राज्यसभा ताकत 10 से घटकर 3 रह गई, जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचाएगी। वहीं दूसरी पंक्ति लीडरशिप कमजोर हुई, क्लीन पॉलिटिक्स की इमेज पर दरार आई और कैडर मनोबल गिरा। पंजाब में संगठनात्मक नुकसान होगा, खासकर 2027 चुनावों से पहले। चूंकि राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का मुख्य कारण पार्टी के मूल सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक जाना बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 साल अपनी जवानी दी, लेकिन अब पार्टी व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रही है और भ्रष्टाचार हटाने वाली पार्टी समझौतों में उलझ गई।

जहां तक व्यक्तिगत कारण की बात है तो चड्ढा ने पार्टी की गतिविधियों से खुद को अलग किया क्योंकि वे उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप अब देश के लिए नहीं, पर्सनल एजेंडे पर चल रही है। समझा जाता है कि यह पार्टी कार्रवाई का दुष्प्रभाव है क्योंकि आप ने उन्हें राज्यसभा उपनेता पद से हटाया और सदन में बोलने पर रोक लगाई, जिसे अशोक मित्तल को सौंपा गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा नेता बनने की कोशिश नाकाम रही, जो तल्खी बढ़ाने वाला था। ये कदम चड्ढा को पंजाब जाने पर मजबूर कर दिए।

राघव चड्ढा के अलावा आप के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय किया, जो कुल 7 सांसदों का समूह बनाते हैं। यह विलय पंजाब और अन्य क्षेत्रों के सांसदों पर केंद्रित था, जिससे आप की राज्यसभा ताकत 10 से घटकर 3 रह गई। भाजपा में शामिल अन्य सांसदों की सूची निम्नलिखित है- संदीप पाठक (राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, आईआईटी ग्रेजुएट), अशोक मित्तल (शिक्षाविद, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी संस्थापक), हरभजन सिंह (क्रिकेटर), स्वाति मालीवाल (पूर्व डीसीडब्ल्यू चीफ), राजेंद्र गुप्ता (ट्राइडेंट ग्रुप संस्थापक, पद्म श्री), विक्रमजीत सिंह साहनी (उद्योगपति, सन फाउंडेशन प्रमुख)। ये ज्यादातर पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, जिन्होंने चड्ढा के नेतृत्व में विलय का हस्ताक्षर किया।।

वहीं, आप ने इसे ऑपरेशन लोटस बताया, लेकिन विलय प्रावधान के तहत कोई अयोग्यता नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा और अन्य आप सांसदों की बगावत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर पंजाबियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया ङ्क पर ट्वीट किया, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया है। केजरीवाल ने इसे पंजाब सरकार को कमजोर करने की साजिश बताया और अमित शाह व नरेंद्र मोदी से अपील की कि यह घिनौना काम पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह पहली प्रतिक्रिया थी, जिसमें उन्होंने सांसदों पर सीधे निशाना साधने से परहेज किया।

वहीं, आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया और कहा कि पंजाब की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया, लेकिन विलय प्रावधान के कारण कानूनी कार्रवाई मुश्किल हुई।

संजय सिंह ने राघव चड्ढा और अन्य 7 आप सांसदों की बगावत को पंजाब के साथ गद्दारी करार दिया। उन्होंने इसे भाजपा का ऑपरेशन लोटस बताया, जिसमें प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर भगवंत मान सरकार को तोड़ने की साजिश रची गई। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि भगवंत मान के अच्छे कार्यों को रोकने के लिए आपने जो किया, पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने दलबदलुओं को चेतावनी दी कि आप ने इन्हें संसद तक पहुंचाया, लेकिन इन्होंने पंजाब जनता को धोखा दिया।

ममता बनर्जी का अदालतों से फटकार खाने का रिकार्ड

योगेंद्र योगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने एक अनूठा रिकार्ड बनाया है। यह रिकार्ड है, अदालतों से फटकार खाने का। देश में शायद ही किसी राज्य की ऐसी सरकार होगी, जिसने अदालतों से ममता सरकार की जितनी डांट खाई होगी। आश्चर्य की बात यह है कि दर्जनों मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवरों में कोई अंतर नहीं आया है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से टकराने का ममता का रवैया ऐसा है मानों पश्चिम बंगाल भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा हो।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में उपद्रवियों द्वारा तीन महिलाएं सहित सात न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि यह इस न्यायालय के अधिकार को भी चुनौती देती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मालदा जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को कारण बताने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई/एनआईए जांच का आदेश दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता ने अफसरों की गलती नही मानने के बजाए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आरोपों का सारा ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ने का प्रयास किया। इससे पहले बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर फटकार लगाई थी।

केंद्र की भाजपा सरकार किसी सरकारी योजना का चुनावी फायदा नही उठा ले, इसी मंशा से ममता सरकार ने कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने में कसर बाकी नहीं रखी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की झाड़ खाने के बाद ममता सरकार परियोजना से बाधाओं को हटाने के लिए मजबूर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को कोलकाता मेट्रो

रेल परियोजना के एक गलियारे के निर्माण में रोड़े अटकाने को लेकर ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को परियोजना की निगरानी करने का निर्देश दिया था। पीठ ने यह भी कहा, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार प्रति काफी उदारता दिखाई है। शीर्ष अदालत ने गहरी नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि यह ऐसा मामला था, जिसमें आपके मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम संवैधानिक हदें लांघते हुए ऐसा काम किया, जिसे आजाद भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री करने का दुस्साहस नहीं कर सका। ईडी ने राजनीतिक रणनीति बनाने वाली मशहूर फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बीच में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद एक फाइल अपने साथ ले गईं। इस मुद्दे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कहा कि किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह में घुसते देखना सुखद नहीं है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था, तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने बंगाल सरकार से पूछा-अतिरिक्त पद बनाने का उद्देश्य क्या था। गड़बड़ी का पता लगने के बावजूद आपने दागी उम्मीदवारों को बाहर क्यों नहीं किया। दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है। पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। पेशे से मॉडल अर्पिता के घर से 49 करोड़ कैश और करोड़ों की ज्वेलरी मिली थी।

साल 2024 में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति हैं और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है। राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में नियुक्त किए जाने तक अपनी नाराजगी जताई। इसके साथ ही सीबीआई और बंगाल सरकार से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर सवाल किए थे। 11 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म भविष्येर भूत पर प्रतिबंध के मामले में ममता सरकार को फटकार लगाते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा कि वे 20 लाख रुपये बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को दें। दरसअल पश्चिम बंगाल में भविष्येर भूत पर बिना वजह प्रतिबंध को लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री

संजय गोस्वामी

बिहार में लगता है कहीं फिर होगा सुशासन की जगह कूशासन ना हो जाए क्योंकि नीतीश सरकार सेवामुक्त हो चुकी है और वहाँ की विपक्ष हमलावर दिखाई दे रही है आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी ये सभी को मालूम थी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है मुख्यमंत्री की रेश में नित्यानंद राय का भी नाम था जो अच्छा आदमी है बोलचाल की भाषा में, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को मुख्य मंत्री पद से सेवामुक्त किया गया और राज्यसभा का सांसद के लिए मनाया गया और फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया इससे छोटे दलों में ही नाराजगी नहीं है बल्कि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग भी इससे नाराज है इसके पहले पूर्व में ऊर्जा मंत्री रह चूके डॉ आर के सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर सवाल किये वो पार्टी को लेकर बेहद चिंताजनक बात है खासकर बिहार को लेकर बीजेपी कई चेहरा थे जो साफ छवि और पढ़े लिखें थे और वर्षो का तजुर्बा था जैसे श्री नन्द किशोर यादव, वहाँ के बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जो पूर्व में वाजपेयी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाना समझ से बाहर है क्योंकि उनके बोल चाल की भाषा पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आती है और शायद बाद में बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार ने जानबूझकर उन्हें बनाने पर जोर दिया ताकि सम्राट चौधरी फिर कोई हरकत करेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को अगले चुनाव में क्या बंगाल के चुनाव में ही देखने को मिलेगा जहाँ ममता दीदी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है जिसमें निर्णायक भूमिका महिलाओ की होंगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस तरह बिहार में महिलाओ को एक सम्मान दिया इससे पश्चिम बंगाल में असर दिखेगा क्योंकि बिहार और बंगाल की सीमा सटी है जहाँ तक कुर्मी वोटर का सवाल है वो भी पश्चिम बंगाल में एंटी बीजेपी को गया है जिसकी संख्या काफी अधिक है इसलिए नीतीश कुमार ने बंगाल चुनाव से पहले ही खेल कर दिया और यूपी में भी बाद में असर आएगा आखिर बिहार में नीतीश कुमार को हटाने की जरुरत क्या थी स्वास्थ्य को लेकर जहाँ तक बात है तो राज्यसभा के सांसद भी नहीं बनाना चाहिए और क्या केंद्र में कोई अहम मंत्रालय मिलेगा सब तो भर गए फूड या उससे सम्बंधित मंत्रालय ही मिलेगा जो नीतीश कुमार लेंगे नहीं जहाँ तक बिहार के विकास की बात है तो बुलडोजर से विकास नहीं होगा क्योंकि इससे गरीबो का रोजगार चौपट होता है जब ईरान में घायल मुर्तज़ा खामनोई बेड पर रहकर भी ईरान की सत्ता चला रहे हैं और आईआरजीसी और वहाँ के मंत्री में टकराव देखने को मिला है उससे ऐ साफ जाहिर है कि देश या राज्य चलाऐ रखने हेतु हेल्थ कोई मुद्दा नहीं होता निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है और जिस तरह नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब बिहार में इन्वेस्टमेंट के कई फाइल को रिजेक्ट किया था जो उनके हिसाब से बिहार जैसे गरीब राज्य में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो तोड़फोड़ होगा जमीनों पर कब्ज़ा होगा और गरीबों को नुकसान होगा इसलिए बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा में लाकर सेल्फ गोल कर लिया है जोड़ तोड़ की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और दूसरे के घर में झंकाना सही नहीं है इससे समय बर्बाद होता है और व्यक्तिगत आरोप लगता है जो राजनीति में गलत है अब आमआदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं सही नहीं है आपको कभी किसी पार्टी ने विश्वास में लिया है तो धोखा देना सही नहीं है अब केजरीवाल के घर का वीडियो दिखाया जा रहा है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि इतना बड़ा महल कैसे बनाया, ये व्यक्तिगत आरोप है इससे बचना चाहिए क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जब भी किसी बिपक्षी पार्टी ने व्यक्तिगत आरोप लगाएं हैं तब तब उस पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है अत: राजनीति में व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए। दरअसल बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो बीजेपी के हाई कमान की बात को माने और सही गलत जो भी हो उसकी मर्यादा का पालन करना है।

सेहत के लिए काफी फायदेमंद है करेले का जूस

करेले में कई औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से परंपरागत चिकित्सा और आयुर्वेद में इसका काफी इस्तेमाल होता है। हालांकि टेस्ट में कड़वा होने के कारण कई लोगों को ये पसंद नहीं होता, लेकिन करेले का जूस रोज पीने से आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल कम करे झ तीन दिन में एक बार सुबह खाली पेट करेले का जूस पियें, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। इस जूस में मोमोर्सिडिन और केरेटिन नाम के दो एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक तत्व होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को मसल्स तक पहुंचाते हैं। भूख बढ़ाए झ अगर आपको कम भूख लगती है तो मुमकिन है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहे, और आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाएं। ऐसे में एक ग्लास करेले का जूस पीने से पाचन तंत्र के रस का स्राव होने लगता है, जिससे भूख खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसके अलावा करेले के जूस कई अनगिनत फायदे हैं।

फिनलैंड में हैं सबसे कम मरीज

यह छोटा सा और बिना शोर शराबे से धड़कने वाला दिल आखिर इतने बड़े 'अटैक' का शिकार क्यों हो जाता है। भारत में जहां दिल के रोगी सबसे ज्यादा हैं, वहां फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां दिल के मरीज सबसे कम हैं। इस संबंध में वहां जब रिसर्च की गई तो इसकी प्रमुख वजह वहां के लोगों के संतुलित खान-पान के तौर पर देखने को मिली। लोगों को भोजन में सावधानी बरतने की जरूरत है।

कान छिदवाने के अनेक फायदे

हिन्दूधर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी परंपराएं विज्ञान पर आधारित है। कान छिदवाना सिर्फ परंपरा नहीं हैं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं, आइए कान छिदवाने से जुड़े वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानते हैं।

मानसिक क्षमता में वृद्धि

वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से होता है। और ब्रेन में ब्लड का सही तरह से सर्कुलेशन होने से आपकी बौद्धिक योग्यता बढती है। इसीलिए पहले के समय में गुरुकुल में जाने वाले हर विद्यार्थी को कान में छेद करना पड़ता था, जिससे उसकी दिमागी क्षमता में वृद्धि होती थी और विद्यार्थी बेहतर ज्ञान की प्राप्ति करता था।

सही रखें प्रजनन क्षमता

कान में छेद करवाना महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि कान के बीच की सबसे खास जगह जिसे प्रजनन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, न केवल पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि महिलाओं की अनियमित पीरियड्स की समस्या को भी दूर करता है।

पुरुषों के लिए फायदेमंद

ये भी माना जाता है कि कान छिदवाने से व्यक्ति को लकवे की शिकायत कभी नहीं होती, साथ ही ये पुरुषो के अंडकोष को और वीर्य को संचित करने में भी लाभदायक होता है। कान छिदवाने से कई प्रकार के इन्फेक्शन, हाइड्रोसील और पुरुषों में ज्यादातर देखी जाने वाली हर्निया की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा व्यक्ति के चेहरे पर चमक और कान्ति आती है और व्यक्ति के रूप में निखार आता है।

आंखों के लिए अच्छा

कान में छेद करवाना आपकी दृष्टि में सुधार करने में मदद करता है। एक्यूपंक्चर के अनुसार, कान के बीच के केंद्रीय बिंदु का संबंध आंखों की रोशनी से होता है। एक्यूपंक्चर में इसी जोड़ पर दबाव डाला जाता है, जिससे आंखों की रोशनी सही रहती है।

कान रखता है स्वस्थ

कान का छेद वाले हिस्से पर दो बहुत जरूरी एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स मौजूद होते हैं, मास्टर सेंसोरियल और दूसरा मास्टर सेरेब्रल। यह प्वाइंट सुनने की क्षमता को सही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के अनुसार टिनिटस के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी कान छिदवाना बहुत अच्छा रहता है।

पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त

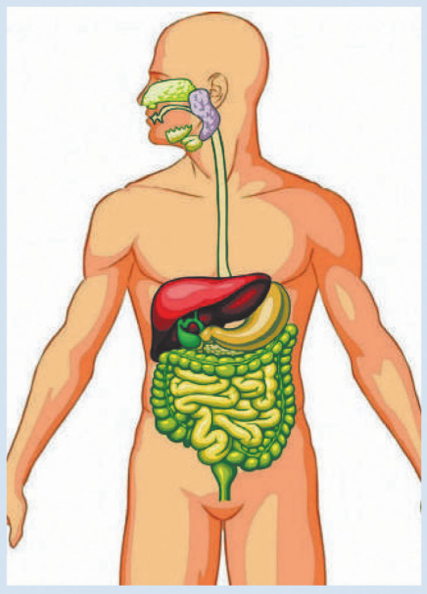

कान छिदवाने का एक बड़ा कारण पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना भी है, क्योंकि इस प्वाइंट पर उत्तेजना से पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से यह प्वाइंट हंगर प्वाइंट का (एक्यूप्रेशर में कहा जाता है) केन्द्र है। हंगर प्वाइंट मानव की पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और मोटापे की संभावना को कम करने में मदद करता है।

कान छिदवाने से जुड़े वैज्ञानिक कारण

कान छिदवाने की परंपरा भारत में काफी पुरानी है। इसके पीछे कई सारी मान्यताएं और रीति-रिवाज हैं, लेकिन अब इंडिया में ही नहीं और भी कई देशों में भी लोग कान छिदवा रहे हैं। महिलाएं तो कान छिदवाती थीं लेकिन अब फैशन के चक्कर में पुरुष भी इसे अपनाने लगे हैं। कान छिदवाने के पीछे हर किसी के अपने विचार है, कुछ लोग कुछ मानते है कि ये एक्युपंचर का विशेष बिंदु होता है जिसका इस्तेमाल उपचार के महत्व से किया जाता है, वहीं कुछ का मानना हैं कि लोग सिर्फ सौंदर्य कि दृष्टि से ही कानों को छिदवाते है। लेकिन यह सिर्फ परंपरा नहीं हैं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं।

हर कदम पर जरूरी है सावधानी

एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडीफिशिएंसी वायरस और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडीफिसिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वह वायरस है, जो एड्स के लिए जिम्मेदार है। यह वायरस शरीर की कुछ खास कोशिकाओं पर हमला करके बॉडी के इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर उसे कमजोर बना देता है। परिणामतः व्यक्ति एड्स और सेक्स संबंधी कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। जब एचआईवी की वजह से किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इस कदर कमजोर हो चुका होता है कि उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसके शरीर में 25 अलग-अलग तरह के इन्फेक्शन डिवेलप हो जाते हैं, तब एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर एड्स पूरी तरह से डिवेलप हो चुका होता है। ऐसे में एड्स की जांच करवाना अनिवार्य हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में एचआईवी वायरस की संख्या नियत लेवल से बढ़ती है।

इनसे नहीं फैलता एड्स

एड्स गले लगने, छूने, छींकने, साथ-साथ खेलने, एक ही बर्तन में खाने या बाथरूम या स्विमिंग पूल शेयर करने से नहीं फैलता। मच्छर के काटने से भी इसके फैलने का खतरा नहीं रहता।

टेस्ट पॉजिटिव होने पर

यदि टेस्ट एचआईवी पॉजिटिव बताता है तो रोगी अपनी मदद के लिए मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। साथ ही एचआईवी की वजह से होने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन यह सब तभी संभव है जब एचआईवी टेस्ट करवाएं।

जांच में एचआईवी पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने के बाद ही रोगी मेडिकल केयर, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर सबका सहयोग भी पा सकता है।

ध्यान रखें

- कोई अपना जिस पर आपको पूरा यकीन हो, उसे बताना क्योंकि परिवार वालों और दोस्तों का सहयोग काफी मायने रखता है।
- रिजल्ट जानने के लिए कोई खास समय निश्चित करें। इसे टालें नहीं क्योंकि टेस्ट रिजल्ट फायदा तभी पहुंचाता है जबकि जल्द से जल्द इसे जान लें।

एचआईवी टेस्ट के स्टेप्स

डॉक्टर के ऑफिस या फिर क्लीनिक जाएं - नर्स या काउंसलर टेस्ट के बारे में बता सकता है। रोगी सवाल कर सकता है और अपने डर को दूर कर सकता है।

एचआईवी से जुड़े टेस्ट ब्लड में कर लिए जाएं- यदि पहला टेस्ट, जिसे एलीसा कहा जाता है, पॉजिटिव आता है (यह एचआईवी पॉजिटिव की निशानी है) तो एक बार फिर से ब्लड चेक होगा। यदि दूसरी बार भी ब्लड टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जो कि वेस्टर्न ब्लॉट कहलाता है, तो वह एड्स है। यह रिजल्ट फिर से क्लीनिक पहुंचता है- इसके बाद नर्स या काउंसलर बताएंगे कि क्या करना है।

पूरी तरह कारगर नहीं दवाएं

एचआईवी से बचाव के लिए अब तक न तो कोई वैक्सीन निकाला जा सका है और न ही अन्य कोई उपाय। हालांकि 'एंटीरेट्रो वायरल्स' जैसी कुछ दवाएं जरूर तैयार की गई हैं जिनसे एचआईवी या सेक्स से जुड़ी अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कुछ और दिन जीने का मौका दिया जा सकता है। हालांकि ये दवाएं महंगी हैं।

इलाज के बजाय बचाव

वक्त बदल चुका है। एड्स के मरीजों को अब पहले की तरह घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसे कंट्रोल करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर के अनुसार बेहतर होगा कि एचआईवी एड्स की चपेट में आने संबंधी सुरक्षा बरती जाए, लेकिन इसके बावजूद यदि इसकी चपेट में कोई आ जाता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है।

जल्द से जल्द सभी जरूरी जांच कराएं और दवाएं शुरू कर दें। खासतौर से ध्यान रखें कि नियमित रूप से जीवन भर एचआईवी एड्स की दवाएं लेते रहें। इसमें कोताही बिल्कुल भी न बरतें। डॉक्टर अनुसार यूं तो दुनिया भर में कई तरह से इसकी जांच की जाने लगी है, लेकिन हमारे देश में अभी ब्लड टेस्ट का ही मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है।

एचआईवी टेस्ट है जरूरी

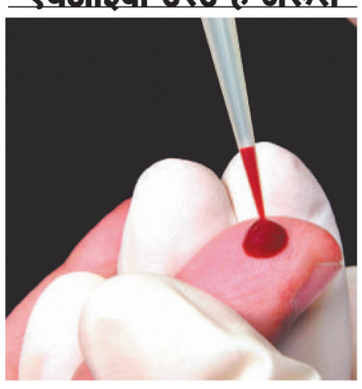

कोई एचआईवी ग्रस्त है या नहीं, जानने का एकमात्र तरीका टेस्ट ही है। खून में मौजूद सीडी4 की संख्या जब 350 से कम हो जाती है तो इसकी जांच कर ली जानी चाहिए। डॉक्टर के अनुसार जितना जरूरी एचआईवी टेस्ट करवाना जरूरी है, उतनी ही जरूरी उससे पहले की काउंसलिंग है। इसके अभाव में मरीज को इस टेस्ट के लिए तैयार करना या फिर इसका रिजल्ट बताना सही नहीं माना जा सकता।

डॉक्टर कहते हैं कि एड्स होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर की हर सलाह पर अमल करें। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आज देश के तकरीबन 300 अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में यह जांच मुफ्त में की जा रही है और एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों को इलाज और दवाएं मुफ्त बांटी जा रही हैं।

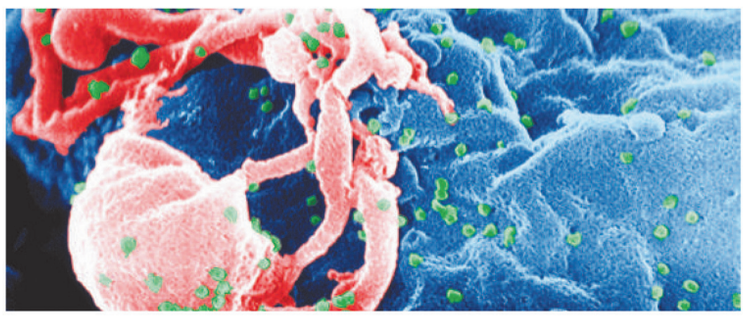

जरूरी है एचआईवी टेस्ट

कोई व्यक्ति एचआईवी ग्रस्त है या नहीं, इसे जानने का एकमात्र तरीका एचआईवी परीक्षण ही है। पूरी तरह से स्वस्थ नजर आने वाला व्यक्ति भी एचआईवी ग्रस्त हो सकता है।

एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं चाहिए

- किसी ऐसे व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, जिसके बारे में निश्चित नहीं कि वह एचआईवी एड्स का शिकार है या नहीं।
- यह पता होना कि जिस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं वह एचआईवी ग्रसित है।
- पहले कभी दोनों में से कोई भी सेक्स से जुड़ी किसी बीमारी के शिकार रहे हों तो भी एचआईवी का खतरा हो सकता है।
- एक से ज्यादा व्यक्तियों से सेक्स संबंध या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध जिसका संबंध पहले कई व्यक्तियों से रहा हो।
- किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन, जो दवाएं लेने के लिए सुई का इस्तेमाल करता हो या फिर उसने दवाएं लेने के लिए कभी किसी अन्य की इस्तेमालशुदा की सिरिंज इस्तेमाल की हो।
- इनमें से किसी भी सवाल का जवाब 'हां' है तो एचआईवी एड्स का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए।

हाई न्यूट्रीशनल डाइट जरूरी

एड्स के मरीजों के लिए मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक जैसी हाई कैलोरी और अंडा, दालें, पीनट्स, बटर, मीट, मछली, दूध जैसी हाई प्रोटीन न्यूट्रीशनल फूड्स दी जाती है।

- एड्स के वैसे मरीज, जिन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें हाई फैट वाली फैटी या फ्राइड चीजें खाने में न दें।
- जिन मरीजों को दस्त की शिकायत रहती है, उन्हें सॉल्युबल फाइबर दे सकते हैं। आलू, केला, फ्रूट जूस, नारियल पानी, इलैक्ट्रोलाइट वगैरह उनके लिए बेहतर डाइट कहा जाता है।

जरूरी यह है कि एचआईवी के जिन मरीजों की दवाएं शुरू कर दी गई हों, उन्हें एक ही बार में पूरी डाइट न दें, बल्कि उन्हें कई बार थोड़ा-थोड़ा करके तरल पदार्थ या खाने को दें।

एचआईवी और सेक्स से जुड़ी अन्य बीमारियों के बीच संबंध

- सेक्स से जुड़ी अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए एचआईवी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वैजिनल, एनल या ओरल सेक्स से भी यह खतरा बना रहता है। इनसे बचने के लिए कंडोम या अन्य सावधानियां बरतना जरूरी है।
- केवल अपने पार्टनर पर भरोसा करके ही एचआईवी से सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। एचआईवी से बचने के लिए इसके कारणों के साथ-साथ इसके बढ़ने की वजहों के बारे में विस्तार से जानें और उसे अमल में लाएं।
- अपने पार्टनर के अलावा किसी से भी सेक्स संबंध न बनाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव न हो।
- असुरक्षित यौन संबंध और जहां-तहां ब्लड टेस्ट करवाने से बचें। इस्तेमालशुदा सुई दोबारा काम में न लाएं।

एक साल में महिलाएं 47 तो पुरुष रोते हैं 7 बार

रोने के फायदे..नहीं होता ब्लड प्रेशर

हंसने के लिए हम कई तरह के फंडे अपनाते हैं और इसको लेकर कई एक्सरसाइज भ्झी की जाती हैं। कहा जाता है कि हंसने से लंबी उम्र होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि रोने से भी ऐसे ही कई फायदे हैं। एक शोध में इसका खुलासा हुआ है। रिसर्च में माना गया है कि रोने से हार्ट और ब्लड प्रेशर, कॉर्डियो जैसी खतरनाक बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। इसे लेकर कुछ लोगों पर सर्वे भी किया जा चुका है।

आंसू बहाना आंखों की सेहत के लिए जरूरी

रोना आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंसू निकलने के बाद हमे साफ देखने में मदद मिलती है। दरअसल आंसू आइबॉल और पलकों को ल्यूब्रिकेट करते हैं और म्यूकस झल्ली को सूखने से बचाते हैं। इतना ही नहीं रोने से किसी भी इंसान का मैगनीज लेवल कम हो जाता है। क्योंकि अगर यह हाई होगा तो चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकान, मेंटल डिसबैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं।

मरते हैं बैक्टीरिया

आंसू एंटी बैक्टीरियल और एंटी वाइरल एजेंट की तरह काम करते हैं। इनमें लाइसोजाइम द्रव पाया जाता है और 90 से 95 प्रतिशत बैक्टीरिया को केवल 5 से 10 मिनट में ही मारने की शक्ति रखता है।

दूर होगी निराशा और चिंता

आंसू चिंता और निराशा को बाहर निकालते हैं। रोने से मन की सफाई हो जाती है। इसके अलावा आंसू स्ट्रेस की वजह से शरीर से निकलने वाले केमिकल को दूर कर देते हैं। आंसू को रोकने से ब्लडप्रेशर, अल्सर और हार्ट का खतरा बढ़ता है।

रोने से कम हो जाता है गुस्सा

- एक शोध के मुताबिक करीब प्रतिशत महिलाओं और 73 प्रतिशत पुरुषों का गुस्सा रोने के बाद कम हुआ ।
- आंकड़ों के मुताबिक महिलाएं एक साल में 47 बार रोती हैं, वहीं पुरुष 7 बार।
- औसत रोने का समय 6 मिनट तक था शोध में ।
- शाम के 7 बजे से 10 बजे तक लोग सबसे ज्यादा रोते हैं।

1 माह पहले वार्निंग देने लगता है हार्ट अटैक

दुनिया में ज्यादातर लोगों की मौत की वजह हार्ट अटैक होती है। कुछ मरीजों को तो हार्ट अटैक के बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन थोड़ी एहतियात बरती जाएं तो दिल के दौरे को टाला जा सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण 1 महीने पहले दिखने लग जाते हैं। खासतौर पर बॉडी में जब यह 6 लक्षण नजर आएं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि यह हार्ट अटैक का यह संकेत हो सकते हैं।

बॉडी में ये 6 लक्षण दिखें तो रहें जरा सावधान

ज्यादा थकान हो तो संभलें

बिना किसी वर्क आउट के थकान होना हार्ट अटैक की दस्तक हो सकती है। दिल को ज्यादा मेहनत की जरूरत तब होती है, जब हृदय धमनियां कोलेस्ट्राल के कारण बंद हो जाती है। अच्छी नींद के बाद आलस और थकान का अनुभव हो और दिन में भी नींद आए तो खतरा है।

सीने में जलन तो रहें सतर्क

सीने में दर्द हार्ट अटैक का शिकार बना सकता है। सीने में दबाव या जलन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सर्दी का बना रहना टेंशन

लंबे समय तक सर्दी बना रहना भी दिल के दौरे की ओर इशारा करता है। सर्दी में कफ के साथ सफेद या गुलाबी रंग का बलगम, फेफड़ों में स्रावित रक्त के कारण हो सकता है।

चक्कर आना भी गंभीर

दिल कमजोर होने से खून का संचार सही से नहीं होता है। ऐसे में दिमाग को आक्सीजन नहीं मिल पाती जिससे चक्कर आने लगते हैं। यह हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार एक गंभीर लक्षण है, जिस पर ध्यान देना चाहिए।

पैरों में सूजन तो है खतरा

दिल को शरीर के अंगों में रक्त पहुंचाने अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शिराएं फूलती हैं और उनमें सूजन आती है। इसका असर पैर के पंजे, टखने और अन्य हिस्से में में नजर आता है। होंठों की सतह का रंग नीला हो जाता है। यह लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलें।

रेसिपी

गट्टे की कढ़ी

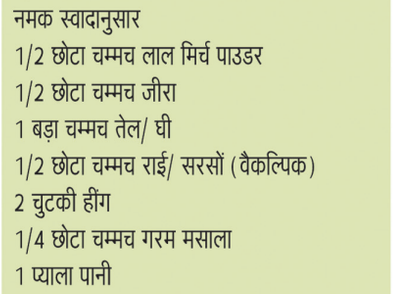

सामग्री-गट्टों के लिए

1 प्याला बेसन
1/4 छोटा चम्मच नमक
2 चुटकी हींग
1/4 छोटा चम्मच अजवाइन
2 चुटकी हल्दी
2 बड़े चम्मच दही
1/2 छोटा चम्मच पिसा धनिया
1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च पिसी हुई
2 बड़े चम्मच पानी बेसन गूथने के लिए
1 छोटा चम्मच तेल बेसन गूथने के लिए
1 बड़ा चम्मच तेल गट्टे भूनने के लिए

सामग्री-झोल के लिए

1 बड़ा चम्मच बेसन
1 प्याला खट्टा दही
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
नमक स्वादानुसार
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच जीरा
1 बड़ा चम्मच तेल/ घी
1/2 छोटा चम्मच राई/ सरसों (वैकल्पिक)
2 चुटकी हींग
1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला
1 प्याला पानी

गट्टे बनाने की विधि

बेसन को छान लें। पानी को छोड़कर बाकी सभी सामग्री इसमें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए कड़ा आटा गूंथ लें। इस आटे को गीले कपड़े से ढककर 5-10 मिनट के लिए रख दें। आटे को चार हिस्सों में बांटें। हाथ में दो बूंद तेल लगाकर एक हिस्से को हथेलियों के बीच में चिकना करें, और लगभग 4 इंच लंबा और 3/4 इंच गोल बेलन जैसा आकार बनाएं। इसी प्रकार बाकी बचे हुए तीन हिस्सों के भी बनाएं। एक बर्तन में लगभग डेढ़-दो प्याला पानी गरम करें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें गट्टों के बेलनाकार टुकड़े डालें और मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक उबालें। उबले हुए गट्टों को पानी से बाहर निकाल लें और पानी को झोल में डालने के लिए अलग रखें। गट्टों के इन टुकड़ों को ठंडा होने दें, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें। गट्टों को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें।

झोल बनाने की विधि

एक कटोरे में बेसन को छान लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाते जाएं। ध्यान रखें कि घोल में बेसन की गुठली ना पड़ने पाए। खट्टे दही को अच्छे से फेटें। दही को बेसन में मिलाएं। एक कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल गरम करे। इसमें जीरा और राई डालें। जब मसाले अच्छे से तड़क जाएं तो हींग और खड़ी लाल मिर्च डालें। मिर्च भुन जाए तो बेसन का घोल और खट्टे दही का घोल डालें। एक उबाल आने तक चलाते रहें, ताकि गुठलियां न पड़ें। उबाल के बाद आंच को धीमा कर दें और कढ़ी को 4-5 मिनट के लिए पकने दें। अगर लगे कि कढ़ी बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा और पानी मिलाएं, और फिर पकाएं। कढ़ी में गट्टों को डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गट्टों को 3-4 मिनट तक कढ़ी में पकाएं। गरम मसाला डालें, मिलाएं और आंच बंद कर दें। रोटी या चावल के साथ गरम परोसें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी आज 594 किमी एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन

मेरठ। मेरठ से प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर देश के विकास का पहिया 29 अप्रैल बुधवार से दौड़ने लगेगा। यूपी के इस सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। फिलहाल छह लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में आठ लेन का किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिले और 519 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे बड़े महानगर भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किमी लंबा एयरस्ट्रिप भी बनाया गया है। इस पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान भी आपात लैंडिंग कर सकेंगे। हापुड़ के ब्रजघाट में गंगा पर एक किमी और इससे आगे रामगंगा पर 720 मीटर लंबे पुलों से इस एक्सप्रेसवे को गुजारा गया है।

आप नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी हैं। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश नहीं होने का एलान किया। उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम अपने देश की न्यायप्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम जो आजाद घूम रहे हैं तो उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बाते उस चिट्ठी में लिखी हैं जो कि हमने जज साहिबा को भेजी है। यह बेहद संवेदनशील मामला है।

शशि थरूर ने माना महिला विरोधी है कांग्रेस : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर एक बड़ा दावा किया है। रिजिजू के अनुसार, शशि थरूर ने एक तरह से यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। यह बयान तब आया जब संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो सका। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था। किरेन रिजिजू ने मीडिया से कहा कि संसद सत्र के बाद उनकी और थरूर की मुलाकात हुई थी। उस दौरान थरूर ने मुस्कुराते हुए रिजिजू से कुछ बातें साझा कीं। रिजिजू के मुताबिक, थरूर ने कहा था, कांग्रेस पार्टी भले ही महिला विरोधी हो सकती है, लेकिन कोई भी महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेगी। रिजिजू ने कहा कि थरूर ने इस वाक्य के जरिए अपनी पार्टी की सच्चाई स्वीकार कर ली।

राजनाथ सिंह ने एससीओ मंच से पाकिस्तान को चेताया

बिश्केक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा विभिन्न आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे समर्थन का स्पष्ट संदर्भ देते हुए मंगलवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सरकार प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद की अनदेखी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस खतरे से निपटने में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंह ने बिश्केक में एससीओ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना दृढ़ संकल्प दिखाया कि आतंकवाद के केंद्रों को न्यायोचित दंड से अब छूट नहीं है। उन्होंने कहा, हमें सरकार द्वारा प्रायोजित उस सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला करता है। सिंह ने कहा, दोहरे मापदंड की कोई गुंजाइश नहीं है और एससीओ को आतंकवादियों को उकसाने, उन्हें पनाह देने और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल का माहौल कर रहे खराबः घोष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि भाटपारा में पिछले कुछ समय से हिंसा का माहौल बना हुआ है। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वहां लगभग हर दिन गोलीबारी और बम धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन चुनाव के दिन स्थिति अलग होगी और लोग शांतिपूर्वक मतदान करेंगे। इसी बीच टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हुए कथित हमले को लेकर भी राजनीति गरमा गई है। दिलीप घोष ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमला सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा हमला करना चाहती तो कई अन्य स्थानों पर ऐसा कर सकती थी, लेकिन उनकी पार्टी का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री ने सिक्किम स्थापना दिवस पर दी 4000 करोड़ रुपए की सौगात

कांग्रेस ने सिक्किम के विकास की अनदेखी की : पीएम मोदी

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंगलवार को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह हिमालयी राज्य के तेज और सतत विकास के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गंगटोक में सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के जश्न के समापन समारोह में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस पुरानी पार्टी ने सिक्किम की विकास परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

उन्होंने कहा सिक्किम ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विज़न को साबित कर दिखाया है। इस कार्यक्रम

में, आपने पूरे हिंदुस्तान को हमारी आँखों के सामने ला दिया है। सचमुच, आपने सबका दिल जीत लिया है। सिर्फ़ मोदी का ही नहीं, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। भारत के प्रति यही सच्ची निष्ठा और देशभक्ति है। इसी के ज़रिए नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होती है,।

केंद्र सरकार, और पीएम मोदी, इको-वेलनेस टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ के इंफ़्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत किया जा रहा है। भारत के पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक्ट ईस्ट, एक्ट फ़ास्ट (पूर्व की ओर बढ़ो, तेज़ी से बढ़ो) के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने सिक्किम की कनेक्टिविटी को किस तरह से बेहतर बनाया है।

उन्होंने कहा सोमवार को रोडशो के दौरान मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी, वह थी सिक्किम की सड़कों की सफ़ाई। दूर-दूर तक कहीं भी गंदगी का नामोनिशान नहीं था... हवा में भी सफ़ाई थी... सड़कों पर भी सफ़ाई थी... आप, सिक्किम के लोग, प्रकृति के सच्चे रखवाले और ब्रांड एम्बेसडर हैं,।

उन्होंने कहा कि सिक्किम पूरब का स्वर्ग और ऑर्किड का बगीचा है, और यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस राज्य की अतुलनीय सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों से भी सिक्किम में ऑर्किड के बगीचों को देखने आने की अपील की।

पीएम मोदी ने कहा केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, सिक्किम में विकास की रफ़्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। पहली बार, रेलवे सिक्किम तक पहुँचने जा रहा है।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री ने सिक्किम में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, और राज्य के 50 साल के राज्यत्व समारोह के समापन समारोह में भी शामिल हुए। ये परियोजनाएँ बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे कई क्षेत्रों को कवर करती हैं।

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान आज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के तहत बुधवार को होने वाला मतदान तय करेगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब भी अपने गढ़ पर कब्जा बनाए रखेगी या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर आखिरकार राज्य सचिवालय 'नबान्न' पहुंचने में सफल होगी। चुनाव के दूसरे चरण के तहत बुधवार को राज्य विधानसभा की 142 सीट के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में उत्तर बंगाल और आस-पास के जिलों में भाजपा की पारंपरिक पकड़ की परीक्षा हुई और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ - कोलकाता, हावड़ा, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान - के मुकाबलों पर नजर रहेगी।

इन इलाकों का परिणाम चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीट जीती थीं, भाजपा ने सिर्फ 18 और 'इंडियन सेक्युलर फ्रंट' (आईएसएफ) ने एक सीट हासिल की थी। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद पांच साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने दक्षिण बंगाल में शानदार जीत हासिल की और आसानी से सत्ता पर कब्जा किया। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए इन इलाकों पर कब्जा बनाए रखना अहम है, जिससे उसके लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रास्ता पूरी तरह से खुला रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''यह हमेशा से हमारा सबसे मजबूत

क्षेत्र रहा है तथा 2021 विधानसभा से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यहां के लोगों ने हमारा साथ दिया।

अगर हम इस क्षेत्र में फिर से जीत दर्ज करते हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी।'' भाजपा की प्रदेश इकाई के एक नेता ने कहा, दक्षिण बंगाल में पकड़ बनाए बिना हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। उत्तर 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा ही असली चुनावी युद्धक्षेत्र हैं। बदलाव यहीं से होगा। भौगोलिक स्थिति इसकी अहमियत को स्पष्ट करती है। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीट, दक्षिण 24 परगना में 31, हावड़ा में 16, नदिया में 17, हुगली में 18, पूर्वी बर्धमान में 16 और कोलकाता में 11 सीट हैं। राज्य में पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान दर्ज होने के बाद बनर्जी ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस पहले ही 100 सीट का आंकड़ा पार कर चुकी है।

यह राज्य में अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने नाम हटाए जाने के मुद्दे को दूसरे चरण का संभवतः सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। उत्तर 24 परगना में मतदाता सूचियों से 12.6 लाख से अधिक नाम हटाए गए, दक्षिण 24 परगना में 10.91 लाख से अधिक, कोलकाता में लगभग 6.97 लाख, हावड़ा में लगभग छह लाख, हुगली में 4.68 लाख और नादिया में लगभग 4.85 लाख नाम हटाए गए।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का सरकार पर दबाव

2029 से लागू करने सर्वदलीय बैठक बुलाएं

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद अब सरकार को महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के बारे में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का उपयोग करने के बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना चाहिए।

मुख्य विपक्षी दल ने महिला आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने के बाद एक बार फिर उठाई है। उसने और कई अन्य विपक्षी दलों ने पहले भी सरकार से यह आग्रह किया था कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार संपन्न होने के बाद महिला आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

सरकार महिला आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद के बीते बजट सत्र में लाई थी, हालांकि यह पारित नहीं हो पाया। विपक्ष ने यह कहते हुए इसका पुरजोर विरोध किया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपा जा रहा है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो

गया है और लोकसभा सीटों के खतरनाक परिसीमन को अंजाम देने की उनकी चाल विपक्षी एकजुटता के कारण बुरी तरह विफल हो गई है, तो प्रधानमंत्री के लिए वह करने का समय आ गया है जो विपक्ष एकजुट होकर मार्च, 2026 के मध्य से लगातार मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 2029 से लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या के साथ कैसे लागू किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, यह संभव है।

यह वांछनीय है। यह जरूरी है। रमेश ने कहा, संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण कभी मुद्दा नहीं था। तब एजेंडा केवल प्रधानमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के लिए परिसीमन था। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत की महिलाओं का उपयोग करने के अपने पापों का प्रायश्चित करें और उन्हें न्याय प्रदान करें।

खेल
प्रमुख समाचार

मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज

मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग का 41वां मैच एक ज़बरदस्त बचने बनाम आगे बढ़ने का मुकाबला होने वाला है, जिसमें मुंबई इंडियंस बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। मुंबई के लिए समीकरण सीधा है, लेकिन मुश्किल भी। पांच बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट 7 मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ बाहर होने की कगार पर है और उसे प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी।

इस सीजन में मुंबई का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है; बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों ही विभाग एक साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। एक और हार टूर्नामेंट में उनके आगे बढ़ने की संभावनाओं को लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकती है। कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व की कड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि उन्हें अपनी खराब प्रदर्शन कर रही टीम को एकजुट करके आगे बढ़ाना है।

रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और मौजूदगी से ऊपरी क्रम को कुछ राहत मिली है, जबकि टीम पारी को संभालने और गति देने के लिए सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी और स्ट्रोक-प्ले पर काफी हद तक निर्भर रहेगी। हालांकि मुंबई की मुश्किलें सिर्फ बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण में वह पैनापन और नियंत्रण देखने को नहीं मिला है, जिसके लिए वह आमतौर पर जाने जाते हैं।

शुरुआती विकेट लेने में नाकामी और बीच के ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने में विफलता ने हाल के मैचों में टीम को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर मुंबई को अपने अभियान को पटरी पर लाना है, तो इन कमियों को दूर करना बेहद जरूरी होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 416 अंक टूटा निफ्टी 23995 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (28 अप्रैल) को गिरावट में बंद हुए। अमेरिका-ईरान संबंधों में हालिया घटनाक्रम के बीच निवेशक सतर्क रुख अपनाया। इससे पहले बाजार सोमवार को तीन दिन की गिरावट के बाद लगभग एक प्रतिशत चढ़कर बंद हुए थे। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक गिरकर 77,094 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,741 अंक तक फिसल गया था। अंत में यह 416.72 अंक या 0.54 फीसदी की गिरावट लेकर 76,886.91 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 24,049 पर खुला। जबकि सोमवार को यह 24100 के ऊपर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 23,957 अंक के इंट्रा-डे लो तक गया। अंत में 97 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट लेकर 23,995 पर बंद हुआ।

रूस से तेल आयात में गिरावट अप्रैल में 20% घटा इंपोर्ट

नईदिल्ली। अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज में संभावित नाकेबंदी के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल जारी है। इसी बीच भारत के लिए एक अहम खबर सामने आई है रूस से कच्चे तेल के आयात में अप्रैल महीने में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल में रूस से कच्चे तेल का आयात घटाकर लगभग 15.7 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया, जो मार्च की तुलना में करीब 20% कम है। मार्च में आयात बढ़ा था, जिसकी वजह अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट और ईरान से जुड़े तनाव थे। रूसी तेल की सप्लाई में कमी की एक वजह यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के एक बड़े टर्मिनल पर लोडिंग में आई बाधा रही। इससे शिपमेंट प्रभावित हुआ और भारत तक पहुंचने वाली सप्लाई घट गई। अप्रैल में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन रूस से तेल खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी रही।

सार्वजनिक वाई-फाई विस्तार में मुफ्त सेवा की इच्छा बड़ी बाधा

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को जारी एक परामर्श पत्र में कहा कि मुफ्त वाई-फाई सेवा की इच्छा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बाधा पैदा कर रही है। भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क का प्रसार विषय पर जारी परामर्श पत्र में ट्राई ने कहा कि 4जी और 5जी मोबाइल डेटा की आक्रामक कीमतों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता ऐसी बन गई है कि वे इंटरनेट संपर्क को लगभग शून्य लागत वाली वस्तु के रूप में देखते हैं। इसी कारण वे पांच रुपए या 10 रुपये की मामूली दर पर भी सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए वाउचर खरीदने में संकोच करते हैं। ट्राई ने कहा, मुफ्त वाई-फाई की व्यापक इच्छा सार्वजनिक वाई-फाई के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बाधा के रूप में काम करती है।

युद्ध के बाद से ईरान में दवाओं की भारी किल्लत

नईदिल्ली। ईरान पर अमेरिका-इजरायल संयुक्त हमलों के बाद हालात गंभीर होते जा रहे हैं और ईरानी दवाखानों में दवाओं की भारी कमी हो गई है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक अमेरिका-इजरायल ने देश के विभिन्न प्रांतों में लगभग 25 फार्मास्युटिकल सुविधा केंद्रों पर हमले किए हैं। टारगेट की सूची में बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं, जिनमें कैंसर, हार्ट रोग, anesthesia और मल्टीपल स्केलेरोसिस की दवाएं बनाने वाले फार्मास्युटिकल केन्द्र के साथ-साथ तेहरान में पाश्चर संस्थान (टीका निर्माता) भी शामिल है। तेहरान के वलीअसर स्क्वायर के पास एक फार्मेसी में कार्यरत डॉ. पेजमान नईम ने स्पुतनिक को बताया, सुगर और हार्ट रोगों जैसी कुछ दवाएं बाजार में अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए ने खोले निवेश के रास्ते और बड़ी संख्या में नौकरी

नीरज कुमार दुबे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता आखिरकार आज नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हो गया, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस समझौते पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मकले की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला महत्वपूर्ण समझौता बताया, जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश प्रवाह और श्रम गतिशीलता के लिए नए रास्ते खोलेगा।

हम आपको बता दें कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने इस अवसर को वैश्विक व्यापार के नए द्वार के रूप में प्रस्तुत किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में व्यापार करना आसान बनाया जा रहा है, नियमों को सरल किया जा रहा है और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि विदेशी कंपनियां यहां आकर लाभ कमा सकें और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें।

यह समझौता विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में अपने सभी 8284 निर्यात उत्पादों के लिए शत प्रतिशत शुल्क मुक्त पहुंच मिल जाएगी। पहले भारतीय उत्पादों पर औसतन 2.2 प्रतिशत तक शुल्क लगता था और कुछ क्षेत्रों जैसे वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर यह शुल्क 10 प्रतिशत तक पहुंच जाता था। अब इन सभी शुल्कों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भारतीय

उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

इसका सीधा लाभ वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को मिलेगा। विशेष रूप से आगरा का चमड़ा उद्योग, जो लंबे समय से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था, अब नई संभावनाओं के साथ उभर सकेगा। औषधि क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिली है क्योंकि न्यूजीलैंड अब वैश्विक नियामकों की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करेगा, जिससे बार बार जांच की आवश्यकता नहीं रहेगी और लागत कम होगी।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को भी इस समझौते से बड़ा लाभ मिलेगा। भारत ने अपने लगभग 70 प्रतिशत शुल्क लाइनों को न्यूजीलैंड के लिए खोल दिया है, जिससे वहां के निर्यातकों को ऊन, लकड़ी, कोयला, शराब, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे उत्पादों में अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा, जहां कीवी, सेब और शहद उत्पादन में तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। लगभग 30 प्रतिशत शुल्क लाइनों को समझौते से बाहर रखा गया है। इनमें दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, चीनी, प्याज, दालें, रत्न और आभूषण तथा धातु क्षेत्र शामिल हैं। इस संतुलन को विशेषज्ञों ने भारत की रणनीतिक सफलता बताया है, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान नहीं होगा।

हम आपको यह भी बता दें कि इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू पेशेवरों के लिए नए अवसर खोलना है। न्यूजीलैंड हर वर्ष 1667 अस्थायी कार्य वीजा देगा और एक समय में अधिकतम 5000 भारतीय पेशेवर वहां काम कर सकेंगे। इससे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और शिक्षा क्षेत्रों के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। निवेश के क्षेत्र में भी यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे भारत में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हम आपको बता दें कि यह समझौता 20 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें वस्तु व्यापार, सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया, तकनीकी बाधाएं, विवाद समाधान और कानूनी ढांचा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस, ई-श्रम साथी एप लॉन्च

श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारीः सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में व्यापक पहल हुई है और चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का

औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-श्रम साथी मोबाईल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, इसलिए उनके योगदान का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा तीनों प्रमुख मंडलों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 5 सितंबर 2008 से अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। एक प्रतिशत उपकर (सेस) से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में श्रमिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, सियान सहायता, नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता, आवास सहायता योजना, निःशुल्क कोचिंग सहायता तथा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना प्रमुख हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6वीं में हर वर्ष 100 बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 31 जिलों के 95 विद्यार्थी 8 जिलों के 14 विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिसे इस शैक्षणिक सत्र से सीटें बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल द्वारा भी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताः कश्यप

रायपुर। बस्तर जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप ने आज नारायणपुर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। कश्यप ने कहा कि सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री कश्यप ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियागांव और भानपुरी क्लस्टर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में कुल 8 करोड़ 09 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाले विभिन्न बुनियादी ढांचागत कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण संपन्न किया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने बनियागांव में सुबह आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने हेतु एक करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी और पूर्ण हो चुके कार्यों को जनता को समर्पित किया। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक करोड़ 27 लाख 76 हजार रुपए की लागत से बनने वाली बनियागांव से कुच्चीगुड़ा सड़क का भूमिपूजन शामिल रहा, जबकि बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूर्ण हुए तुरपुरा की सीसी सड़क और केशरपाल के अहाता निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया।

वन मंत्री कश्यप ने 809.71 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन व लोकार्पण

वन मंत्री अपने भ्रमण के दौरान दोपहर भानपुरी में आयोजित द्वितीय चरण के कार्यक्रम में विकास की एक बड़ी झड़ी लगी। यहां कुल 6 करोड़ 61 लाख 95 हजार रुपए की विकास परियोजनाओं पर मुहर लगी, जिसमें 6 करोड़ 23 लाख 09 हजार रुपए की लागत से बनने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भानपुरी से पदरपारा, फरसागुड़ा से खासपारा और भानपुरी- चित्रकोट मार्ग से धनवाड़पारा तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।

साथ ही मुरकुची हाई स्कूल में प्रार्थना शेड निर्माण का भूमिपूजन करने के साथ-साथ विधायक निधि और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भानपुरी, तारागांव और विश्रामपुरी क्लस्टर में नवनिर्मित सीसी सड़कों एवं पुलिया निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी गई।

लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी पर होगी सख्त कार्रवाईः वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जनहितैषी कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभागीय आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की।

बैठक में नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार और सीमांकन जैसे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। मंत्री वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। यदि समय-सीमा में कार्य नहीं होता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी।

इसी तरह मंत्री वर्मा ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एग्रीस्टेक के तहत जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए । साथ ही, नक्शा प्रोजेक्ट और जियोरिफ्रेसिंग के कार्यों में हो रहे विलंब को अगले 03 महीनों के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आबादी पट्टा वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारी 31 जुलाई तक सभी लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी तरह आगामी समय को देखते हुए ?आपदा प्रबंधन की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नही होना चाहिए।

गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत, शर्मा के विशेष प्रयासों से 13.80 करोड़ जारी

रायपुर। वैवाहिक सीजन एवं आगामी फसल की तैयारियों के बीच गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना, राम्हेपुर (कवर्धा) द्वारा किसानों को 13.80 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही चालू पेराई सत्र में अब तक कुल 71.29 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। समयबद्ध भुगतान से सहकारी व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। चालू पेराई सत्र में कारखाने ने उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 2,55,818 मीट्रिक टन गन्ना पेराई एवं 3,09,120 क्विंटल शक्कर उत्पादन किया गया है। यह सफलता किसानों के सहयोग, प्रशासनिक मार्गदर्शन और कारखाने की कुशल कार्यप्रणाली का परिणाम है।भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों और श्रमिकों के हित में निरंतर कार्य कर रहा है। इसमें एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी आधारित भुगतान, शासन द्वारा प्रदत्त बोनस वितरण, रियायती दर पर शक्कर उपलब्धता, उन्नत बीज एवं कृषि मार्गदर्शन, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किसानों के लिए सर्वसुविधायुक्त बलराम सदन तथा मात्र 5 रूपए में गरम भोजन की कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जिले की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनकर उभरा है। यह किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी, फसल विविधता को बढ़ावा, हजारों लोगों को रोजगार तथा पीडीएस के लिए सस्ती दर पर शक्कर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय पर भुगतान, बेहतर प्रबंधन और किसान-केंद्रित योजनाओं के चलते यह कारखाना सहकारी मॉडल की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ जिले के समग्र विकास को भी गति मिल रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

ईडी का भाजपा नेता के घर जाना नया प्रयोगः बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नेता अजय चंद्राकर के भाई के घर ईडी की छापेमारी हुई है। बताया जाता है भारत माला घोटाले के संदर्भ में छापे मारे गये। क्या इस छापे के पीछे एक मात्र यही कारण है। यह संयोग है या भाजपा का अपने ही नेता के यहां ईडी भेजने का नया प्रयोग है, जो भाजपा दूसरे दलो के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने ही दल में शामिल करता है। वह अपने ही

वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर के यहां ईडी भेज रही इसके बहुत मायने है। बड़े-बड़े घोटाले करने के बाद सैकड़ो लोग भाजपा में शामिल हुये उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गयी, क्लीन चिट दे दिया गया। अजय चंद्राकर तो भाजपा के ही नेता है, फिर उनके घर ईडी क्यों गयी होगी? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस छापे से साफ हो रहा कि भाजपा का एक वर्ग अजय चंद्राकर को निपटाने में लगा है, या फिर अजय चंद्राकर की जबान बंद करने के लिए ईडी हो भेजा है। दरअसल अजय चंद्राकर के विधानसभा में तीखे सवालों से भाजपा नेतृत्व डरा हुआ है। वे अपनी पार्टी की सरकार को आईना दिखाते है। विधानसभा में साय सरकार के 2047 के डाक्यूमेंट को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया। इसीलिए अजय चंद्राकर के घर ईडी भेजकर जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है।

राजधानी में बढ़ता अपराध असहनीय हो गया हैः शुक्ला

रायपुर। राजधानी में बढ़ता अपराध असहनीय हो गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी में कल फिर चाकूबाजी से एक युवक की हत्या कर दी गयी। एक नाबालिक गंभीर रूप से घायल है। राजधानी में रोज अपराधिक घटनाये बढ़ते जा रही, अपराधी बैखोफ घूम रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि

कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के बाद भी अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। रोज हत्या, लूट, चाकूबाजी, की घटनाये हो रही है। पुलिस अपराधो को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस का अपराधो को रोकने के लिए कोई प्रयास भी नहीं दिख रहा। पुलिस केवल टेऊफिक के चालान करने, वसूली करने में व्यस्त है। राजधानी में अपराधों का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे राजधानी में रोज हो रही अपराधिक घटनाये सरकार की विफलता को बताती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कमिश्नरेट लागू कर दिया लेकिन कोई भी प्रभाव अपराधियो पर पड़ते हुये नहीं दिख रहा है। कमिश्नरी प्रणाली लागू कर के शहर में एक आईजी, एक डीआईजी, एक एसपी, तीन एडिशनल एसपी की तैनाती कर दी गयी है।

निंदा प्रस्ताव, कानून पर बाध्यकारी प्रभाव नहींः अकबर

रायपुर । पूर्व केबीनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान जारी कर कहा है कि लोकसभा में 131 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो पाने के पश्चात् भाजपा लोगों को गुमराह करना चाह रही है। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 को पारित हो चुका है तथा लोकसभा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत

महिला आरक्षण का कानून बन चुका है। महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने परिसीमन करने भाजपा का षडयंत्र सफल नहीं हुआ तो वह गैर भाजपा पर्टियों पर महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने का झूठा आरोप लगा रही है जबकि महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास है लेकिन व्यवहार में यह निर्णय मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। यदि सरकार चाहे तो किसी विशेष मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकती है। सामान्यत: विशेष सत्र राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा के लिए, विश्वास मत/बहुमत परीक्षण, बजट या अनुपूरक बजट पारित करने के लिए, प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था संकट या विशेष कानून पारित करने के लिए बुलाया जाता है।

बोरे-बासी दिवस का आयोजन करे सरकारः वर्मा

रायपुर । मजदूर दिवस पर पूरे प्रदेश में बोरे-बासी उत्सव के आयोजन की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि बोरे-बासी केवल भोजन मात्र नहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा है, मेहनतकश छत्तीसगढ़िया आम जनता की जीवन शैली है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 1 मई

2020 से श्रमिकों के सम्मान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के तौर पर आयोजन की शुरुआत की थी जिसे भाजपा की सरकार ने धूमिल कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार का दायित्व जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही प्रथा, परंपरा, संस्कृति, रीति-रिवाज और खानपान के संरक्षण और संवर्धन का भी है। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस तो मनाती है, लेकिन छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से भाजपा नेताओं को हिकारत है। प्रदेश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़े इस पर्व को भाजपा की सरकार मिटाना चाहती है, जबकि लोग खुद अपनाने लगे हैं। सरकार दुर्भावन और पूर्वाग्रह छोड़कर आगामी 1 मई को बोरे-बासी दिवस का आयोजन करे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की प्राथमिकता में चंद पूंजीपति मित्रों का मुनाफा है।

जिला चिकित्सालय में 7 वर्षीय गौरव का हुआ सफल टॉन्सिल ऑपरेशन

रायपुर। मुंगेली जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने 07 वर्षीय बालक गौरव साहू को लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्या से राहत दिलाई। जिला बेमेतरा के ग्राम बंदी निवासी गौरव साहू पिछले एक वर्ष से टॉन्सिल में बार-बार संक्रमण की समस्या से परेशान था। इस कारण उसे निगलने में कठिनाई होती थी और उसका वजन भी लगातार कम हो रहा था। परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ओपीडी में कान, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश सत्यपाल को दिखाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने गौरव को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित बताया और शीघ्र ऑपरेशन की सलाह दी। इसके पश्चात डॉ. कमलेश सत्यपाल , डॉ. राजेश कुमार बेलदार एवं ओटी स्टाफ की टीम द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद बालक पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है। अब उसे खाने-पीने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और उसका स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो रहा है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण अब स्थानीय स्तर पर ही जटिल उपचार संभव हो रहे हैं, जिससे मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता कम हो रही है। यह सफलता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की दक्षता का प्रमाण है।

सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावी पहल

छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक मजबूत और संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है, वहीं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभागीय योजनाएँ प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इन प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

सरल प्रक्रिया, सहज लाभ

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अलग सीनियर सिटीजन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से आयु और पात्रता

का सत्यापन कर सीधे लाभ प्रदान किया जा रहा है, इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुलभ बनी है।

सम्मानजनक जीवन का आधार

प्रदेश के राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में संचालित 27 वृद्धाश्रम निराश्रित एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय बनकर उभरे हैं। वर्तमान में यहां 675 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएँ नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल रहा है।गंभीर रूप से बीमार एवं बिस्तर पर आश्रित वृद्धजनों के लिए राज्य में 13 प्रशामक गृह संचालित हैं। वर्तमान में रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, रायगढ़ एवं बेमेतरा में 140 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इन केंद्रों में निरंतर देखभाल, उपचार सहयोग और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिससे संवेदनशील स्थिति में भी उन्हें मानवीय और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा के तहत पात्र वृद्धजनों को नियमित पेंशन दी जा रही है। बीपीएल एवं एसईसीसी वंचन समूह के वृद्धजनों को 500 रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 680 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। यह सहायता उनके दैनिक जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को मजबूती देती है।

नई ऊर्जा का संचार

वरिष्ठ नागरिक को सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर अधिकतम 6900 रुपए तक के उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, छड़ी, श्रवण यंत्र, चश्मा, ट्राइसाइकिल सहित अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, ।

ब्लॉक कमेटियों में महिलाओं की उपेक्षा से कांग्रेस का राजनीतिक पाखण्ड उजागरः सांसद वर्मा

रायपुर। राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने बिलासपुर जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के गठन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है। श्रीमती वर्मा ने कहा कि जो पार्टी अपने संगठन के भीतर महिलाओं को तय मापदण्ड के अनुसार जगह नहीं दे सकती, वह देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या सुनिश्चित करेगी?

राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि बिलासपुर जिले के 11 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की सूची कांग्रेस के दोहरे चरित्र का प्रमाण है। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि संगठन में 30 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं को मात्र 13 प्रतिशत पदों पर ही सीमित कर दिया गया है। 341 पदाधिकारियों की सूची में केवल 43 महिलाओं को स्थान मिलना यह दर्शाता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है! श्रीमती वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंचों से महिलाओं के सशक्तीकरण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसे लुभावने नारे देते हैं; लेकिन जब संगठन में जिम्मेदारी देने की बारी आती है, तो महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जो पार्टी अपने संगठन में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे पा रही, वह लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रति कितनी ईमानदार होगी, यह प्रदेश की जनता देख रही है।

राज्यसभा सांसद श्रीमती वर्मा ने कहा कि यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सूची में जिन महिलाओं को स्थान मिला है, उन्हें भी केवल कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर पर रखा गया है, प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका वाले पदों से महिलाओं को दूर रखकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.